चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 25 अप्रैल-01 मई 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

देश में पानी का भीषण संकट

सूखता भविष्य

शशि शेखर/शफीक आलम

ऐसा कई वर्षों से कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा. अब, यह विश्व युद्ध कब होगा, कैसे होगा, इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन हमारे खुद के देश में पानी को ले कर लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं. पिछले दिनों महाराष्ट्र के लातूर शहर में कई जगह धारा 144 लगाई गई. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक तलाब के पानी की सुरक्षा के लिए बन्दूकधारी गार्ड तैनात किए गए. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि फिलहाल देश के 12 राज्यों के करीब 35 फीसदी जिले भयंकर सूखे की चपेट में है. खेती-बारी तो छोड़िए, पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो रहा है. लातूर में ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है, ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके.

ऐसे हालात में अब जरा देश के एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री का बयान पढ़िए. क्या सूखा हमारे हाथ में है? जब भगवान की मर्जी होगी, बारिश होगी. बारिश नहीं होगी, तब हम वो काम करेंगे जो हमें करना है. यह बयान है देश के एक बड़े और ताकतवर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का. एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री जब ऐसा बोलते हैं, तो मान लेना चाहिए कि ये सरकार का आधिकारिक स्टैंड है. यानी, सूखे को ले कर नरेंद्र मोदी सरकार क्या सोच रखती है, यह इस बयान से पता चलता है. दूसरी तरफ स्थिति यह है कि देश के 12 राज्यों में भीषण सूखा है. केंद्र सरकार ने खुद माना है कि देश के दस राज्य सूखे की चपेट में हैं. पूरे देश के करीब 40 फीसदी जिलों में पानी की कमी हो गई है. बुंदेलखंड में पानी की कमी से बुरा हाल है. तेजी से पलायन हो रहा है. ओड़ीशा में किसानों की हालत दयनीय हो गई है. कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध सूख चुका है. इधर, केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर अभी तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है. दूसरी तरफ, पानी की बर्बादी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चिंतित हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ी घोषणा सुनने को नहीं मिली है.

मुंबई हाई कोर्ट ने भी बीसीसीआई को डांट लगाते हुए पूछा था कि जहां एक तरफ देश में सूखा है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, ऐसे में आईपीएल के नाम पर करीब 50 लाख लीटर पानी कैसे बहाया जा सकता है? कोर्ट ने यह सवाल किया कि खेल जरूरी है या लोगों का जीवन. ध्यान देने वाली बात है कि जहां महाराष्ट्र के लातूर में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहीं महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल मैच में लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल सिर्फ मैदान की प्यास बुझाने के लिए किया जाता. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आप सूखे की हालत से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं. सूखे को लेकर स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से ये सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात के लिए भी फटकारा कि मनरेगा के तहत सूखा प्रभावित राज्यों को पर्याप्त धन का आवंटन क्यों नहीं किया? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी इन राज्यों में औसतन 48 दिन का ही काम मनरेगा के तहत मिल पा रहा है, जबकि कानूनन यह सौ दिनों का होना चाहिए. दिलचस्प तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जब तक आप पर्याप्त धन का आवंटन नहीं करेंगे तब तक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होगा. कोर्ट ने यह भी बताया कि गुजरात के भी 256 गांव सूखाग्रस्त हैं. गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से इन सूखाग्रस्त राज्यों को मनरेगा के तहत उतना धन भी नहीं भेजा गया है जो कानूनन उनका हक था.

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने अबतक क्या कदम उठाए हैं? इसमें केंद्र समेत तमाम राज्य सरकारें शामिल हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अधिकांश तालाबों का हाल अतिक्रमण की वजह से खराब हो चुका है. गांवों में अब कुएं रहे नहीं. राज्य सरकारें अब कच्ची की जगह पक्की नहरें बना रही हैं. अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक योजना शुरू करने की बात कही थी. यह नदी को जोड़ने की योजना थी. आज वह योजना कहां है, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम. अगर उस योजना पर काम हुआ होता, तो आज इतनी खराब स्थिति देखने को नहीं मिलती.

सरकार के मुताबिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में मनरेगा के तहत 50 अतिरिक्त दिन का काम देने की बात कही गई है. लेकिन, जब सरकार के आंकड़े ही खुद बताते हैं कि औसतन 48 दिनों से ज्यादा का काम नहीं मिल पाता और सरकार ने मनरेगा के तहत आवंटित धन भी संबंधित राज्य सरकारों को नहीं दिया है तो ऐसे में अतिरिक्त 50 दिन का काम देने की बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? इसके अलावा, सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में डीज़ल सब्सिडी देने, बीज सब्सिडी देने, अतिरिक्त चारा उपलब्ध कराने की बात कही है. लेकिन, यह सब आज कहीं भी जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है. फिर, सवाल यह भी है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो. मनरेगा के तहत वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण की बात तो सरकार करती है लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है. आज, हालत यह है कि महाराष्ट्र में जल शिविर के निर्माण के बाद भी महाराष्ट्र का 2 फीसदी से भी कम जमीन सिंचित भूमि के तहत आता है. सवाल है कि विभिन्न सरकारों की ओर से बारिश के पानी को सहेजने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं?

अभी मानसून आने में डेढ़ महीने की देरी है. वैसे तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस बार वर्षा सामान्य से अधिक होगी, लेकिन इन डेढ़ महीनों के दौरान लातूर, बुन्देलखंड जैसे इलाकों का क्या होगा? सूखा करीब-करीब आधे से अधिक राज्यों को प्रभावित कर रहा है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कई इलाकों में पानी के लिए लोग सुबह से लाइन में लगते हैं, फिर भी उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है. लातूर के लिए तो स्पेशल ट्रेन से पानी भेजा जा रहा है लेकिन वह भी नाकाफी है. मराठवाड़ा से लोग पलायन कर के मुंबई में शरण ले रहे हैं. वहां घाटकोपर के मैदान में, खुले आसमान के नीचे लोग जीवन जीने को मजबूर हैं. पानी की कमी की वजह से स्कूल, अस्पताल सब जगह हाहाकार मचा हुआ है. लातूर में तो बकायदा पुलिस निगरानी में पानी का वितरण हो रहा है क्योंकि पानी को लेकर लोगों के बीच झड़पें होनी शुरू हो गई हैं. बुंदेलखंड के बांदा में अगर आप जाते हैं तो वहां करीबन सत्तर फीसदी घरों में आपको ताले लटके मिलेंगे. वजह, वहीं पानी का अभाव. मजबूरी में लोग घर में बूढ़े मां-बाप, जानवरों को छाड़ कर पलायन कर रहे हैं. यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत दक्षिणी बिहार के भी कई इलाकों में पानी की कमी की खबरें आ रही है. ओड़ीशा में भी सूखे की स्थिति है. यहां के 21 जिलों के 139 ब्लॉक में सूखे की स्थिति है. बालासोर, बोलांगीर, कटक, गंजाम, जाजपुर, मयूरभंज, पुरी में किसानों की हालत खराब है. किसानों ने तो अब सार्वजनिक तटबंधों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि उनके खेतों को पानी मिल सके. कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध में पानी ही नहीं है. उत्तरी (शेष पृष्ठ 2 पर)

अगर मानसून फेल हुआ तो!

जैसे-जैसे सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, देश में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है. देश के कई राज्य भयानक सूखे की चपेट में हैं. जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि रेत निचोड़ कर प्यास बुझाने की कहावत अक्षरशः सही साबित हो रही है. ऐसे में सब की निगाहें एक अच्छे मानसून पर टिकी हुई हैं. अगर इस वर्ष मानसून अच्छा हो गया तो इससे न सिर्फ प्यासी धरती को राहत मिलेगी बल्कि पिछले दो वर्षों से बारिश की कमी के कारण प्रभावित खरीफ फसल की पैदावार में भी वृद्धि होगी. लेकिन, मानसून एक ऐसी पहेली है जिसे मौसम वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा सके हैं. लिहाज़ा, इसकी भविष्यवाणी का कोई भी कारगर तरीका नहीं खोजा जा सका है. कुछ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को अनियमित मानसून का प्रमुख कारण मान रहे हैं तो कुछ अल नीनो को. अल नीनो की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान काफी ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है.

बहरहाल, जिस तरह से भारत की नदियां भारत की जीवन रेखा हैं, बिल्कुल उसी तरह मानसून भारतीय जीवन का एक अटूट हिस्सा है. देश में 75 प्रतिशत पानी की आमद बारिश से होती है, जो कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है. ऐसे में ख़राब मानसून के ख्याल मात्र से किसानों का दिल दहल जाना कोई अनोखी बात नहीं है. दरअसल, इसमें कोई शक नहीं कि मानसून की बारिश प्रत्येक वर्ष सामान्य नहीं होती और इसमें क्षेत्रीय विविधता भी होती है. इसलिए देश में सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठाना लाज़मी है कि यदि इस वर्ष मानसून अच्छा नहीं हुआ तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी? पहले ही से कर्ज़ की वजह से आत्महत्या कर रहे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

दरअसल, ये सवाल इसलिए भी अहम हैं क्योंकि भारत में ऐसे बहुत कम अवसर आये हैं जब लगातार दो सालों तक मानसून नाकाम रहा है. वर्ष 1986-87 के बाद वर्ष 2014-15 में एक बार फिर देश में लगातार दो वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई है. रोबर्ट डी कप्लान अपनी किताब मानसून में लिखते हैं कि अनियमित मानसून के कारण वर्षा पर निर्भर देश के तकरीबन दो तिहाई कृषि और इस कृषि से जुड़े किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं. क्योंकि अगर बारिश बहुत कम होगी तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी. नतीजे में कृषि पैदावार प्रभावित होगी और किसानों की आमदनी पर बट्टा लगेगा, खाद्य सामग्री की कीमतों भी बढ़ोतरी होगी. ज़ाहिर है, इसका व्यापक असर होगा लेकिन इसकी सबसे अधिक मार कम आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगी.

बहरहाल, पिछले कुछ वर्षों से मानसून की नाकामी को पहले से अधिक महसूस किया जा रहा है. हालांकि, हरितक्रांति के बाद से ख़राब मानसून का वह प्रभाव देखने को नहीं मिला, जो आज़ादी से पहले देखने को मिलता था, लेकिन अर्थशास्त्र के जानकार मानते हैं कि 1980 के दशक के आख़री वर्षों के बाद से अनियमित मानसून की वजह से खाद्य उत्पादन में अस्थिरता आई है. एक अन्य अध्ययन के मुताबिक सूखे वाले वर्षों में कृषि पैदावार में स्पष्ट कमी देखने को मिली है. 1979-80, 1987-88 और 2002-03 के सूखे वाले वर्षों में खाद्यान उत्पादन में 3 से 13 प्रतिशत तक की गिरवट दर्ज की गई. जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि मानसून की स्थिति पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. इसका नतीजा यह होता है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कृषि पैदावार में कमी एक सामान नहीं होती. मिसाल के तौर पर वर्ष 2005-06 में बिहार में खाद्यान उत्पादन में 38 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई तो उसी वर्ष राजस्थान में यह गिरावट 13 प्रतिशत थी. इसलिए मानसून की नाकामी पूरे देश में एक जैसी नहीं रहती. भारतीय मानसून की एक विशेषता यह भी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ कर देश का हर राज्य कभी न कभी सूखे से प्रभावित जरूर रहता है. सूखे के कारण भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है. खास तौर पर, अगर लगातार कई वर्षों से मानसून की बारिश कम होती है तो जलाशयों और जल के दूसरे स्रोतों में पानी की कमी होगी. नतीजतन, भूजल रिचार्ज नहीं होगा. यह स्थिति गंभीर रूप से सूखा प्रभावित जिलों में देखने को मिल रही है, जहां कुएं और हैंड पंप सूख गए हैं और सरकार को दूसरी जगहों से वहां पानी की आपूर्ति करनी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

देश में पानी का भीषण संकट
सूखता भविष्य

पृष्ठ 1 का शेष

कर्नाटक में लोग टैंकर के भरोसे हैं जो सप्ताह में सिर्फ तीन दिन पीने का पानी देता है. मैसूर और बंगलुरु जैसे शहरों की हालत ये है कि अब सिर्फ दो महीने का ही पानी बचा है. दो महीने बाद, यदि बारिश नहीं हुई तो, इन शहरों में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सकेगा. 31 मार्च, 2016 तक के देश के 91 प्रमुख जलाशयों की संग्रहण स्थिति को देखे तो 91 प्रमुख जलाशयों में 39.651 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण है. दिलचस्प रूप से यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का महज 25 प्रतिशत है. इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता का लगभग 62 प्रतिशत है. अब जरा पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के जलाशयों में मौजूद पानी की हालत देखिए. पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं. इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की

यह सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा दिन हमें देखना क्यों पड़ रहा है? इसमें गलती किसकी है? ये समस्या सिर्फ भौगोलिक या पर्यावरणीय कारणों से पैदा हुई है या फिर यह समस्या मानवजनित भी है. इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये समस्या सिर्फ और सिर्फ मानवजनित ही है. इसमें अगर पर्यावरणीय कारण भी है तो वो भी मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ही खराब हुई है.

कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी यानी केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में हैं. इन जलाशयों में अभी कुल संग्रहण क्षमता का सिर्फ 21 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 40 प्रतिशत था. मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं. इस क्षेत्र में 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं और इनमें संग्रहण क्षमता का सिर्फ 32 प्रतिशत पानी मौजूद है. वहीं, दक्षिणी क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में सीडब्ल्यूसी की निगरानी में 31 जलाशय हैं और इसमें इन 31 जलाशयों की कुल क्षमता का महज 17 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है. यानी, आप समझ सकते हैं कि देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर अभी क्या है?

यह सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा दिन हमें देखना क्यों पड़ रहा है? इसमें गलती किसकी है? ये समस्या सिर्फ भौगोलिक या पर्यावरणीय कारणों से पैदा हुई है या फिर यह समस्या मानवजनित भी है. इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये समस्या सिर्फ और सिर्फ मानवजनित ही है. इसमें अगर पर्यावरणीय कारण भी है तो वो भी मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ही खराब हुई है. सबसे पहले तो हमने अपने पारंपरिक जल स्रोतों, पानी को संचित करने के तरीकों को खोते गए. वनों की कटाई, बेतहाशा बढ़ते कंक्रीट के जंगलों ने बाकी का काम कर दिया. तालाबों पर अवैध कब्जे से पानी का ये भी एक स्रोत खत्म होता चला गया. खेती के बदलते तरीकों, रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग, खेती के लिए भूजल का दोहन, इस सब ने भी पानी का भरपूर दोहन किया. मसलन, महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में गन्ने की खेती करना कहां तक जायज माना जा सकता है, जिसमें भारी मात्रा में पानी की खपत होती है. इसके अलावा, पैकेज्ड वाटर (बोतलबंद पानी) के व्यापार ने भी भूजल का दोहन किया है. एक तरफ जहां देश में लगातार पानी की कमी हो रही है वहीं दूसरी तरफ बोतलबंद पानी का कारोबार खरबों रुपये का हो चुका है. ये कंपनियां आमतौर पर भूजल का ही इस्तेमाल करती हैं. सवाल है कि जिस देश में करोड़ों लोगों को पीने का पानी इस वजह से नहीं मिल रहा हो कि जमीन के अंदर का पानी सूख गया है, वहां सरकार कैसे पानी के कारोबार को चलने दे रही है? यह अमानवीय है, शर्मनाक है और जीने के मूल अधिकार का हनन भी है.

अब, जरा हम एक काल्पनिक तस्वीर देखते हैं. मान लीजिए, अगले एक महीने के भीतर आने वाला मानसून फेल हो जाता है, गर्मी का पारा इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या होगा? देश के 40 फीसदी जिलों के लोगों, किसानों और जानवरों की हालत क्या होगी? जाहिर है, फसल नहीं होगी. फसल नहीं होगी तो किसान ज्यादा संख्या में आत्महत्या करेंगे. अनाज, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे. क्या इस देश की जनता इस सबके लिए तैयार है? चौथी दुनिया ने देश में सूखे के हालात का एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है. बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से चौथी दुनिया संवाददाताओं ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, उसे इस अंक में लिया गया है. ये रिपोर्ट बताती है कि सूखे की स्थिति कितनी भयावह है. और, अगर समय रहते सरकारों ने उचित कदम नहीं उठाए और अगर दुर्भाग्य से मानसून फेल हुआ या कमजोर हुआ तो आने वाला समय न सिर्फ किसानों बल्कि हमारे और आपके लिए भी बहुत भयावह होने वाला है. ■

सभी फोटो–**प्रभात पाण्डेय**

अगर मानसून फेल हुआ तो...

पृष्ठ 1 का शेष

पड़ रही है. अब सवाल यह उठता है कि सरकार वर्षा की कमी के कारण पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए क्या कर सकती है? इस क्षेत्र में सबसे पहले उसे मानसून की भविष्यवाणी की प्रणाली को त्रुटिरहित बनाना होगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर तो मानसून का सही अनुमान लगाना तकरीबन संभव हो गया है, लेकिन इसका फायदा किसानों को इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि क्षेत्रीय स्तर अभी भी इसकी सही भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है. इसलिए कभी अतिवृष्टि के कारण तो कभी अल्पवृष्टि की कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. नतीजतन, क़र्ज़ में डूबे किसान मजबूरन आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं. इस स्थिति से निपटने का एक तरीका कृषि पर आश्रित किसानों को वैकल्पिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना भी है. सरकारी स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. हालांकि, इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच के बड़े हिस्से को कृषि पर केंद्रित रख कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन देश में नव उदारवादी आर्थिक नीति अपनाये जाने के बाद से उपेक्षा का शिकार और देश के 60 प्रतिशत लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध करने वाले इस क्षेत्र के लिए ठोस एलान उन्होंने भी नहीं किया.

दरअसल, मानसून के कारण सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगर सरकार ने समय रहते उचित क़दम नहीं उठाये तो न सिर्फ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आत्महत्या भी जारी रहेगी और देश में पीने के पानी का संकट और गहरा हो जाएगा. ■

नदी जोड़ो योजना का क्या हुआ?

भारत एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से भी विविध देश है. रेगिस्तान, समंदर, पहाड़ से ले कर समतल जमीन है. नदियों की प्रचुरता है. हर साल देश के एक हिस्से में जहां बाढ़ का पानी कुछ राज्यों को बर्बाद करता है, वहीं सूखे की मार भी पड़ती है. नदियों का अधिकाश पानी समुद्र में जा कर न खेती लायक बचता है, न पीने लायक. यानी, भौगोलिक विविधता की वजह से इस देश में पानी मुसीबत का कारण बनता जा रहा है. दूसरी तरफ, पर्यावरणीय कारणों से पानी के प्राकृतिक स्रोत पर असर तो पड़ ही रहा है, बारिश के पानी को भी संजोने में हम असफल रहे हैं. वन की कटाई, कंक्रीट के बढ़ते जंगल, भू–क्षरण, प्रदूषण की वजह से मौसम चक्र में परिवर्तन आदि ने मिल कर भारत जैसे देश में पानी की कमी पैदा कर दी है. बावजूद इसके, हमारी नदियों में इतना पानी जरूर है जिससे कि लातूर या बुन्देलखंड जैसे इलाके में पड़ने वाले सूखे से निबटा जा सके. इसके लिए बहुत पहले से नदी जोड़ो योजना की बात कही जा रही है. अटल विहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की बात कही थी. इस योजना का मकसद सिर्फ इतना था कि नदियों को जोड़ने से पानी का सही जगह पर, सही वक्त पर सही इस्तेमाल हो सकेगा. 15 साल बाद भी इस योजना पर केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है. हालांकि, कुछ राज्यों में ऐसी शुरुआत हुई है. आंध्रप्रदेश में गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने के लिए योजना बनी है. इस योजना से कृष्णा डेल्टा क्षेत्र के किसानों को बहुत राहत मिलेगी. गोदावरी का बहुत सारा पानी हर साल बंगाल की खाड़ी से मिल कर बर्बाद हो जाता है. गौरतलब है कि जहां देश में एक तरफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक कावेरी नदी के पानी को लेकर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पानी को ले कर हमेशा आपस में उलझे रहते हैं, वहां आज भी नदियों को जोड़ने की योजना पर ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा है. अगर, इस योजना को ईमानदारी से पूरा कर लिया जाता तो आने वाले समय में बाढ़ और सूखे से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती थी. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 08
25 अप्रैल–01 मई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

देश में पानी का भीषण संकट

सूखता भविष्य

वाइब्रेंट गुजरात का है यह हाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

गुजरात सरकार को सितंबर 2015 में ही मालूम हो गया था कि राज्य में सूखे के हालात हो सकते हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे रही. जब लाखों लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया, पीने के पानी की किल्लत होने लगी, तब जाकर राज्य सरकार की आंख खुल और उसने राज्य के 623 गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित किया. वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. क्या सरकारों की अब यह आदत हो गई है कि जब कोर्ट का डंडा चलेगा तभी वह कुंभकर्णी नींद से जागेंगी, चाहे लोग मरते रहें. सवाल यह है कि जब गुजरात सरकार को सितंबर में ही यह मालूम था कि राज्य में सूखे के हालात हो सकते हैं, तो उसने राज्य में सूखा घोषित करने के लिए एक अप्रैल 2016 का इंतजार क्यों किया?

ऐसे में यह सवाल भी खड़ा होता है कि वाइब्रेंट गुजरात का यह कैसा विकास है और किसके लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वह कहीं भी जाते हैं, तो गुजरात का उदाहरण जरूर देते हैं. भाजपा के विकास मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात का यदि यह हाल है, तो भाजपा को देश को बताना चाहिए कि क्या यही गुजरात का असली मॉडल है? देश में गुजरात को भाजपा विकास का प्रतीक बताती रही है. विकास के उस प्रतीक की हालत यह है कि सरकार को 6 महीने पहले जानकारी थी कि प्रदेश के कई जिले सूखा ग्रस्त हैं, बावजूद इसके राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. जब सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई तब जाकर उसने 623 गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित किया. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सूखे को लेकर आप बिलकुल गंभीर नहीं हैं. इसके जवाब में जब गुजरात सरकार ने कहा कि सूखा घोषित किए जाने में देरी चुनाव की वजह से हुई तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर चुनाव होंगे, तो क्या राज्य का सारा काम बंद हो जाएगा.

राज्य में सूखे की हालत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र में पानी का भयंकर संकट है. सूखे की वजह से वहां के हालात इतने खराब हैं कि वहां के जलाशयों में सिर्फ दस फीसदी पानी शेष बचा है. इतने पानी से किसी तरह अधिक से अधिक दो महीने गुजर जाएंगे. लेकिन इसके बाद क्या? इस सवाल का जवाब फिलहाल सरकार के पास नहीं है. पानी का संकट कच्छ और उत्तरी गुजरात में भी है. नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख चुके हैं और जलाशयों में अब उतना पानी नहीं बचा है कि लंबे समय तक लोगों की प्यास बुझ सके. गुजरात का पाटन क्षेत्र सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित है. सरकार ने बनासकांठा, पाटन और अमरेली सहित अन्य जिले के कलेक्टरों से सूखे के हालात की जानकारी मांगी है. ■

भाजपा के विकास मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात का यदि यह हाल है, तो भाजपा को देश को बताना चाहिए कि क्या यही गुजरात का असली मॉडल है? देश में गुजरात को भाजपा विकास का प्रतीक बताती रही है, विकास के उस प्रतीक की हालत यह है कि सरकार को 6 महीने पहले जानकारी थी कि प्रदेश के कई जिले सूखा ग्रस्त हैं, बावजूद इसके राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई तब जाकर उसने 623 गांवों को सूखा ग्रस्त घोषित किया.

feedback@chauthiduniya.com

दक्षिण भारत की हालत भी दयनीय है

चौथी दुनिया ब्यूरो

दक्षिण भारत के तीन राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त माना गया है. आंध्र और तेलंगाना की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है. साल 2015-16 के लिए तेलंगाना के 443 ग्रामीण मंडलों में से 231 को सूखाग्रस्त माना गया था. तेलंगाना ने जहां सूखे से राहत के लिए केंद्र सरकार से एक हजार करोड़ रुपये की मांग की थी, वहीं उसे जनवरी 2016 में उसे केंद्र सरकार से 791 करोड़ रुपये मिले. महबूब नगर, मेंडक और निज़ामाबाद जिले के सारे मंडल सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं. रंगा रेड्डी के 37 में से 33, करीम नगर के 57 में से 19, नालगोंडा के 59 में से 22 और वारंगल के 51 में से 11 मंडल सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं. दूसरी तरफ, खरीफ सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश के 670 मंडलों में से 196 मंडल सूखाग्रस्त घोषित हुए. कर्नाटक में स्थिति यह है कि वहां की नदियां तक सूख गई हैं.

गांवों की हालत दयनीय है. लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं. लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है. मैसूर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में लोग सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर टैंकर से पानी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं. चित्रदुर्गा में लगातार पांच साल से पड़ रहे सूखे की वजह से यहां पीने के पानी की भी किल्लत हो गई है. तुमकुर के पावागडा में फ्लोराइड युक्त पानी के लिए भी मारामारी मची हुई है. इस ताल्लुका से कोई नदी नहीं गुजरती है इसलिए यहां की स्थिति और भयावह है. यहां के भूजल में भारी मात्रा में फ्लोराइड मिला हुआ है. पीने का पानी यहां विलासिता की एक वस्तु बनकर रह गया है. कलबुर्गी जिले की हालत भी कोई अलग नहीं है. यहां 1972 के बाद सबसे बड़ा सूखा पड़ा है. यहां भी पीने का पानी नहीं है. करवार क्षेत्र के 197 गांवों में पानी की कमी है. पिछले 20 सालों में आए सबसे बड़े सूखे की वजह से उत्तर कन्नड़ जिले के कई गांवों में लोगों को पीने का पानी मुहैय्या नहीं हो पा रहा है. भूजल स्तर के नीचे जाने और जल स्त्रोत में समुद्र के खारे पानी के मिल जाने की वजह से स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है.

कर्नाटक के लगभग 600 से अधिक गांवों पर सूखे की भयंकर मार पड़ी है. इन ग्रामीणों के लिए पीने के पानी का एकमात्र साधन पानी का टैंकर रह गया है जो कि सप्ताह में सिर्फ तीन बार उनके गांव आता है. राज्य के तेरह बांधों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है. पानी की कमी का आलम यहां ऐसा है कि गांव वालों को अपने यहां होने वाली शादियां तक रोकनी पड़ रही हैं. जाहिर है कि जब पीने का पानी ही नहीं है तो नहाने की बात सोचना भी किसी गुनाह से कम नहीं है. इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है. राज्य के दस हजार से अधिक कुएं सूख चुके हैं. सूखे का आलम यह है कि मैसूर और बंगलुरु जैसे शहरों के लिए भी केवल जून तक का ही पानी शेष है. इसके बाद के लिए बारिश पर ही निर्भरता है. ■

कहां गए हमारे तालाब?

चौथी दुनिया ब्यूरो

देश में सूखे की वजह से जो जल संकट पैदा हुआ है, उसके लिए केवल मानसून/वर्षा को दोषी ठहराना ठीक नहीं है. क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आए हैं, जब देश के किसी एक क्षेत्र में लगातार दो वर्षों तक मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई हो. देश के जिन क्षेत्रों में जल संकट का इतिहास रहा है, वहां लोगों ने जल प्रबंधन के अपने स्थानीय उपाय निकाले थे. उन उपायों में तालाबों का निर्माण और प्राकृतिक झीलों का संरक्षण शामिल था. तालाबों और झीलों से जहां एक तरफ पीने और खेतों की सिंचाई का पानी मिलता था, वहीं इनमें लंबे समय तक पानी संचित रहने की वजह से आसपास का भूजल स्तर भी ऊंचा रहता था. इन झीलों और तालाबों के आसपास के कुएं बहुत विकट स्थिति में ही सूखते थे. दरअसल, ऐसे जल स्रोत हर शहर और हर गांव में होते थे, जहां बरसात के बाद भी पानी जमा रहता था. लेकिन, अब उनमें से बहुत से जल स्रोतों पर अवैध क़ब्ज़ा जमा लिया गया है, या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए लोगों ने उन जलाशयों को कूड़ादान बना कर कूड़े से पाट दिया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के उच्च न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप तक करना पड़ा. अगस्त 2006 में एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण बुनियादी मौलिक अधिकार, यानि जीवन का अधिकार है, जिसकी व्यवस्था संविधान की धारा 21 में दी गई है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि प्राकृतिक जल स्रातों की न सिर्फ रक्षा होनी चाहिए, बल्कि अगर वे इस्तेमाल में नहीं हैं तो उन्हें बहाल करके इस्तेमाल योग्य बनाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि जल स्रोतों की रक्षा और बहाली की ज़िम्मेदारी सरकार की है. इस संबंध में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें गांवों में हाइवेज से लगे तालाबों और पानी के स्रोतों पर ताक़तवर बिल्डर माफियाओं द्वारा अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया जाने का मामला उठाया गया था. हालांकि, याचिकाकर्ता ने जिस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उसमें उसे राहत नहीं मिली.

सितम्बर 2014 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई खंडपीठ ने अपने फैसले में सरकार को आदेश दिया था कि सरकार जल स्रोतों पर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दे. अगस्त 2014 में ही जल संचय से संबंधित एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दिल्ली जल बोर्ड को वहां मौजूद प्राचीन बावलियों और तालाबों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए यह टिप्पणी की थी कि यदि जल की कमी ऐसे ही होती रही तो जल के लिए युद्ध होने में बहुत समय नहीं है. अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर देहात के अधिकारियों को आदेश दिया कि जिले में जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकें. इस तरह के कई और फैसले हैं, जो जल स्रोतों की रक्षा और उनकी बहाली की बात करते हैं. अखबारों में छपी रिपोर्टों के मुताबिक देश में कई जगहों पर तालाबों और झीलों की बहाली का काम भी चल रहा है. सरकारें भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसके लिए क़दम बढ़ा रही हैं. मिसाल के तौर पर वर्ष 2004 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कृषि से जुड़े जल स्रोतों की बहाली के लिए आरआरआर (रिपेयर, रेनोवेट एंड रिस्टोर) नामक एक बड़ी योजना शुरू की थी, जिसके लिए दसवीं योजना में वित्त आवंटन को बढ़ा दिया गया था. उसी तरह, मौजूदा वर्ष के बजट में जल संचय को मनरेगा से जोड़ने की बात की गई है.

लेकिन, पिछले कुछ दशकों से हो रहे अंधाधुंध शहरीकरण ने जल स्रोतों को कूड़ेदान में परिवर्तित कर दिया है. सबसे हैरानी वाली बात यह कि जल संपदा पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी 2012-13 की रिपोर्ट में कहा कि देश के अधिकतर जल स्रोतों पर नगर निगमों और पंचायतों ने अतिक्रमण किया हुआ है. 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के भीतर उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख जल स्रोत अतिक्रमण का शिकार हुए. अब जब सरकारी संस्थाओं का यह हाल है तो भूमाफिया और दूसरे अतिक्रमणकारियों का कहना ही क्या.

इसमें कोई शक नहीं है कि पारंपरिक जल स्रोतों के अनगिनत लाभ हैं. जहां इससे एक तरफ किसानों को सिंचाई का सस्ता साधन मिल जाता है, वहीं यह पर्यावरण के अनुकूल भी है. इससे जल संचय भी होता है और भूजल भी रिचार्ज होता रहता है. लिहाज़ा, अगर इन स्रोतों को पूरी तरह से बहाल कर लिया जाता है तो जल संकट की गंभीरता में ज़रूर कमी आएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो, जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जल युद्ध प्रारंभ होने में अधिक समय नहीं है. हालांकि, इन अदालती फैसलों के बाद भी अतिक्रमण का सिलसिला जारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश में पानी का भीषण संकट

सूखता भविष्य

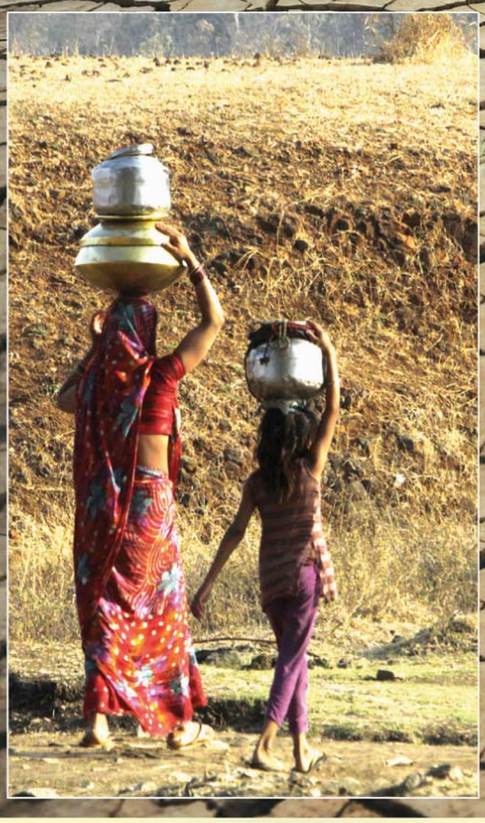

सूखाग्रस्त राज्य और उसके सूखाग्रस्त जिले 2015-2016

राज्यों के नाम/कुल जिला	कुल जिला/ताल्लुका	जिला का नाम
कर्नाटक (30)	27(खरीफ) (126 ताल्लुका) 12 (रबी) (62 ताल्लुका)	बंगलुरू ग्रामीण, रमानागरा, कोलार, चिकबल्लापुर, तुमकुरु, चित्रादुर्गा, दावनागिरी, चमाराजनगर, मैसूर, मांड्या, बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी, यादगिर, बिदार, बेलागवी, बगलकोट, विजापुरा, गडग, हवेरी, धारवाड, शिवमोग्गा, हासन, कोडागू, उत्तरी कन्नड, चिकमंगलुरु, बल्लारी, कोप्पल, रायचूर, कलाबुर्गी, यादगिरी,बीदार, बेलागवी, बगलकोट, विजयपुरा, गडक, हवेरी, धारवाड.
छत्तीसगढ़ (27)	25 (110 ताल्लुका)	रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमतरा, राजनंदगांव, कबीरधाम, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, रायगढ़, जशपुर.
मध्यप्रदेश (42)	42	कटनी, शहडोल, उमारिया, अनूपपुर, टीकमगढ़, रीवा, जबलपुर, सीधी, सागर, दमोह, सिवनी, सिंगरौली, श्योपुर, छतरपुर, भिंड, पन्ना, सतना, डिंडोरी, शिवपुरी, मंदसौर, मुरैना, झाबुआ, भोपाल, उज्जैन, नीमच, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, खंडवा, रतलाम, नरसिंहपुर, गुना, बैतूल, बुरहानपुर, आगर मालवा, सीहोर, इंदौर,धार, शाजापुर, हरदा, छिंदवाड़ा, देवास.
महाराष्ट्र (36)	21 (15747 गांव)	नासिक, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभानी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, यवतमाल, नागपुर, गढ़चिरौली.
ओड़ीशा (30)	21 (139 ब्लॉक)	अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बोलांगिर, बुंधगढ़, कटक, देवगढ़, ढेंकानल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, झारसुगडा, कलाहांडी, कंधमाल, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, नवापारा, नवरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगढ़ा संबलपुर,सोनेपुर, सुंदरगढ़.
आंध्र प्रदेश (13)	10 (359 मंडल)	अनंतपुर, चित्तूर, वाईएसआर कड़प्पा, कुरनूल, प्रकासम, , एसपीएसआर नेल्लौर, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कृष्णा.
उत्तर प्रदेश (75)	50	संत रवि दास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थ नगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैज़ाबाद, गोंडा, कन्नौज, बाराबंकी, संत कबीर नगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महाराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर.
तेलंगाना (10)	7 (231 मंडल)	महबूब नगर, मेंडक, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी, नालगोंडा, , करीमनगर, वारंगल.
झारखंड (24)	24	रांची, खूंटी, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सराइकेला, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा, दुमका , गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, जमतारा, गिरीडीह.
राजस्थान	19 (14487 गांव)	अजमेर (541), बांसवाड़ा (1514), बारा (1070), बाड़मेर (2206), भीलवाड़ा (1126) चित्तौड़गढ़ (94), चुरु (249), डूंगरपुर (988), हनुमानगढ़ (100), जयपुर (603), जालौर (407), जैसलमेर(114), झुंझुनू (130), जोधपुर (527), नागौर (139), राजसमंद(1063), उदयपुर (2498), पाली (291), प्रतापगढ़ (827).

भारत वर्ष के नक्शे पर पिछली बारिश का हिस्सा

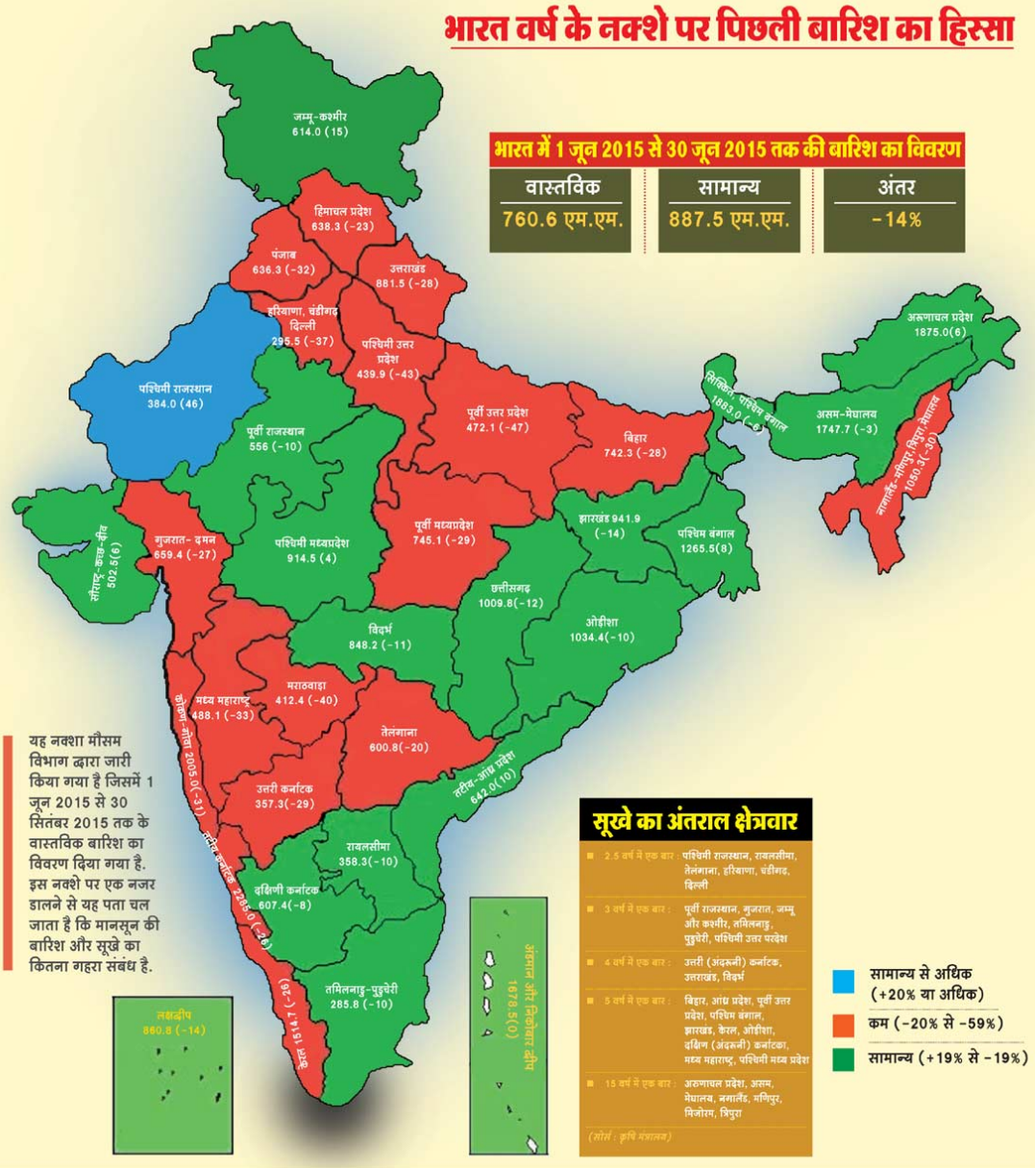

भारत में 1 जून 2015 से 30 जून 2015 तक की बारिश का विवरण

वास्तविक	सामान्य	अंतर
760.6 एम.एम.	887.5 एम.एम.	-14%

यह नक्शा मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसमें 1 जून 2015 से 30 सितंबर 2015 तक के वास्तविक बारिश का विवरण दिया गया है. इस नक्शे पर एक नजर डालने से यह पता चल जाता है कि मानसून की बारिश और सूखे का कितना गहरा संबंध है.

सूखे का अंतराल क्षेत्रवार

- 2.5 वर्ष में एक बार : पश्चिमी राजस्थान, रायलसीमा, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली
- 3 वर्ष में एक बार : पूर्वी राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
- 4 वर्ष में एक बार : उत्तरी (अंदरूनी) कर्नाटक, उत्तराखंड, विदर्भ
- 5 वर्ष में एक बार : बिहार, आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, ओड़ीशा, दक्षिण (अंदरूनी) कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश
- 15 वर्ष में एक बार : अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा

(सोर्स : कृषि मंत्रालय)

सामान्य से अधिक (+20% या अधिक)
कम (-20% से -59%)
सामान्य (+19% से -19%)

इस बार उम्मीद करें झूम कर बरसेगा मानसून

अल-नीनो एक असामान्य मौसमी पैटर्न है, जो दक्षिण अमेरिका के तट से सटे ऊष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण पैदा होता है. आमतौर पर कुछ वर्षों के अंतराल के बाद पूर्वी प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा (इक्वेटर) क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है जिसकी वजह से दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में असामान्य मौसमी बदलावों के साथ भारतीय उप-महाद्वीप में हर साल आने वाला दक्षिण-पश्चिमी मानसून भी प्रभावित होता है.

अल नीनो की स्थिति उस समय पैदा होती है, जब वाणिज्य हवाएं (ट्रेड विंड्स) कमज़ोर पड़ जाती हैं या फिर उल्टी दिशा में चलने लगती हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग की गर्म जल धाराएं अपना रुख पूर्व की तरफ मोड़ लेती हैं. यह गर्म जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र के शीतल जल को विस्थापित कर देती है. जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान बढ़ जाता है, और यह कई वायुमंडलीय बदलावों का कारण बनता है. अल-नीनो की वजह से पूरी दुनिया की सामान्य मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है. इसकी वजह से कम वर्षा क्षेत्रों में अधिक और अधिक वर्षा क्षेत्रों में कम बारिश होने लगती है. आम तौर पर यह देखा गया है कि अल-नीनो वाले वर्षों में मानसून की बारिश कम होती है. एक अध्ययन के मुताबिक 65 प्रतिशत अल-नीनो वाले वर्षों में मानसून की बारिश कम या सामान्य से कम (96 प्रतिशत से कम) रहती है, जबकि 71 प्रतिशत अल-नीनो के बाद के वर्षों में यह बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक (96 प्रतिशत से अधिक) होती है. इसलिए भारतीय मौसम विभाग प्रशांत महासागर के मौसमी बदलाव को लेकर सतर्क रहता है. और इस पर हमेशा अपनी नज़रें बनाए रखता है.

पिछले दो वर्षों से भारत में मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है. इन दो वर्षों में भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान ऊंचा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष अप्रैल से ही पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने लगा था. जिसने जुलाई आते-आते प्रचंड रूप धारण कर लिया और सितंबर में अपने चरम पर पहुंच गया. हालांकि सितंबर 2015 के बाद अल-नीनो की स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी, लेकिन अभी भी वहां समुद्र तल का तापमान सामान्य से अधिक है. लेकिन सितम्बर के बाद से इसमें जो गिरावट आनी शुरू हुई थी वह पैटर्न अब तक जारी है. इसलिए उम्मीद करनी चाहिए प्रशांत महासागर में अल-नीनो की स्थिति नहीं बनेगी और भारत में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होगी, जिसकी उम्मीद मौसम विभाग ने भी अप्रैल 2016 में अपनी पहली भविष्यवाणी में की है. मौसम विभाग के तकनीकि आकलन से देश के आम लोगों के साथ-साथ सरकारों की उम्मीदें भी जागी हैं कि बारिश आई तो उनका सिरदर्द कम हो. बारिश झूम कर आई तो फिर नेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदार-दलालों की बल्ले-बल्ले होगी, क्योंकि खूब बारिश हुई तो बाढ़ आएगी और बाढ़ उनके लिए फिर से कमाई का जरिया बन कर आएगी. आम आदमी को तो कभी सूखा झेलना है तो कभी बाढ़. ■

बुंदेलखंड

देश में पानी का भीषण संकट
सूखता भविष्य

सभी फोटो- प्रभात पाण्डेय

बुंदेलखंड का नाम आते ही जेहन में एक ऐसी तस्वीर उभरने लगती है जो बहुत भयावह है और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भू-भाग वाला यह हिस्सा कभी अपने विशालकाय सरोवरों और चंदेलकालीन कुओं के लिए जाना जाता था लेकिन अब सूखा और अकाल इसका परिचय करा रहे हैं. यहां हर तरफ़ बस सूखे का शोर है. वही सूखा जो राजनीतिक दलों के लिए सियासत की ज़मीन और बुन्देलों के लिए जी का जंजाल बन चुका है. प्राचीन हों या फ़िर मौजूदा, कमोवेश यहां के सारे जलस्रोत विफ़ल हो चुके हैं.

इसरार पठान

आधा दर्जन नदियां, दो दर्जन से अधिक बांध, सैकड़ों तालाब, बेशुमार प्राचीन कुंए, ढेर सारे ट्यूबवेल और अनगिनत हैंडपंप! ये सब मिलकर भी बुंदेलखंड की नियति नहीं बदल सके, जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक मक्कारी ने स्थाह बना दिया. बुंदेलखंड आज अकालग्रस्त है. कभी अपनी चंदेलकालीन जल धरोहरों पर इतराने वाला यह क्षेत्र अब बेहद बेबस और लाचार नज़र आ रहा है. सूखे की चपेट में आकर यहां के विशालकाय बांध जबाब दे चुके हैं और नदियों की गर्म रेत सूरज को आंख दिखा रही है. हैंडपम्पों का गला अब पूरी तरह सूख चुका है और ट्यूबवेल हिचकियां ले रहे हैं. कुएं कूड़ेदान और तालाब खेल के मैदान बन चुके हैं. इन बिगड़े हालातों का ही नतीज़ा है कि कुछ गांवों में बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी और कहीं नौजवान पलायन की राह पर निकल लिए. कहीं सूखे के चलते तयशुदा शादियां रद्द करनी पड़ीं, तो कुछ गांव में पानी कुंआरों की बढ़ती संख्या का सबब बना हुआ है. किसी करिश्मे की दरकार में टकटकी लगाए बुंदेलखंड के गांवों की पथराई उम्मीदों आंखें, सूखे खेत और चारागाहों में पड़े मृत मवेशियों के अस्थिपंजर एक ऐसे बुंदेलखंड की शिनाख़्त कर रहे हैं जो आज पूरी तरह थक चुका है, टूट चुका है और बिखरने की कगार पर है.

बुंदेलखंड का नाम आते ही जेहन में एक ऐसी तस्वीर उभरने लगती है जो बहुत भयावह भी है और डरावनी भी. उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भू-भाग वाला यह हिस्सा कभी अपने विशालकाय सरोवरों और चंदेलकालीन कुओं के लिए जाना जाता था लेकिन अब सूखा और अकाल इसका परिचय करा रहे हैं. यहां हर तरफ़ बस सूखे का शोर है. वही सूखा जो राजनीतिक दलों के लिए सियासत की ज़मीन और बुन्देलों के लिए जी का जंजाल बन चुका है. प्राचीन हों या फ़िर मौजूदा, कमोवेश यहां के सारे जलस्रोत विफ़ल हो चुके हैं. बात यदि नदियों की करें तो यमुना, बेतवा, केन, धसान, उर्मिल, शहजाद, जामिनी, रोहनी, उतारी और सजनाम जैसी हर छोटी-बड़ी नदी जल विहीन हो चुकी है. कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर नदियों में सिर्फ रेत बची है जबकि कुछ नदियां विलुप्त होने को हैं. महोबा की चन्द्रावल नदी इसका एक बड़ा उदाहरण है. प्रशासनिक मक्कारी और संरक्षण के अभाव में पूरी तरह विलुप्त हो चुकी इस नदी के जीर्णोद्धार पर अब तक करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा चुके हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यह नदी वर्षों पहले अस्तित्वविहीन हो चुकी थी. यदि इन आंकड़ों को सच मान लें तो एक बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर उसमें बांध बनाने की आवश्यकता ही क्या थी और उस बांध से अभी तक कितना लाभ मिला है. सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूखे से निपटने के नाम पर यहां सिर्फ क़ागजी खानापूर्ति की गई और उसके नाम पर मिले धन को ठिकाने लगाया गया है. आंकड़ों की बाज़ीगरी का शिकार केवल यहां की नदियां ही नहीं हुईं बल्कि बुंदेलखंड में बनाए गए करीब दो दर्जन बांधों के निमार्ण पर भी यही फलसफा अपनाया गया है. आगौसी पम्प कैनाल, पारीक्षा, माटाटीला, मझगवां, उर्मिल, गंगउ, बरयारपुर, लहचूरा, रैथट, पहारी, कबरई, मौदहा, क्योलारी, उतारी, रंगावन, ओहन, गुन्ता, खप्पर, सजनम, पुंज, चन्द्रावल, गोविन्दसागर, शहजाद, जामिनी और अर्जुन सरीखे सभी सूखे पड़े बांध नीति निर्धारकों की चूक और प्रशासनिक नीयत को साफ उजागर कर रहे हैं. अरबों रुपये की लागत डकार जाने के बाद भी ये बांध सूखे क्यों हैं इसका जवाब आज किसी के पास नहीं.

कभी बुंदेलखंड के मुख्य जल स्रोत रहे चंदेलकालीन तालाब और कुओं का हश्र तो जग जाहिर है. रखरखाव के अभाव में सिसकियां लेतीं इन प्राचीन धरोहरों का हैंडपंप और ट्यूबवेल तकनीक ने गला ही घोंट दिया है. लोगों का मानना है कि इस नई तकनीक के आने से बुंदेलखंड का दोहरा नुकसान हुआ. इनके वजूद में आने के बाद जहां प्राचीन जल स्रोतों को उपेक्षित कर दिया गया, वहीं इस तकनीक के सहारे हमारा वह भंडारण भी समाप्त हो गया जो भूमिगत था. नतीजे के तौर पर आज कुएं कूड़ेदान और तालाब खेल के मैदान बन चुके हैं. एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक बुन्देली धरती की छाती में पग-पग पर खोंसे गए लाखों हैंडपम्पों में से 90 प्रतिशत या तो पानी देने में असमर्थ हैं या फिर उनसे निकलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है. इस संस्था की रिपोर्ट बताती है कि यहां कुछ हैंडपम्पों में पानी का टीडीएस 2500 से 3000 तक पहुंच गया है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है. इस क्षेत्र में पानी की किल्लत और अकालग्रस्त हालातों का अंदाजा यहां के सुनसान गांव और सूखे खेतों से लगा सकते हैं. सरकारी आंकड़ों से ठीक विपरीत यहां की सच्चाई स्तब्ध कर देने वाली है. झांसी जनपद के बबीना विकासखंड में शामिल खजराहा खुर्द गांव के बच्चों ने सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पेयजल बंदोबस्त के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था. ग्रामीणों की मानें तो पढ़ाई से ज्यादा पानी जरूरी है. यहां पानी की कीमत के बारे में वे गड्ढे और पोखरें भी बयान कर रहे हैं जिनका पानी कीचड़युक्त होने के बाद भी ग्रामीणों के लिए वरदान बना हुआ है. सूखे का प्रतिकूल असर केवल यहां की पेयजल व्यवस्था पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इस जल संकट ने बुंदेलखंड में कुंआरों की संख्या भी बढ़ा दी है. हमीरपुर और बांदा जनपद के बहुत सारे गांव आज इस कथन के गवाह बने हैं. गुसियारी हमीरपुर और माखनपुर बांदा सरीखे गांव आज कुआंरों से भरे पड़े हैं. सूखे ने बुंदेलखंड से पलायन करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी है. आज तीन करोड़ की चौथाई आबादी दिल्ली, मुम्बई, गुजरात, हरियाणा और पंजाब का रुख कर चुकी है. महोबा के सिजहरी, पलका, मामना और बांदा जिले के दर्जन भर गांवों में लटकते ताले इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं. इन गांवों में अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है या फिर वे वृद्ध दिखाई देते हैं जो पथराई आंखों में किसी करिश्मे की आस लिए घरों के बाहर दरबान बने बैठे हैं. सूखे ने बुन्देलखंडी जनता को ही हलकान नहीं किया, बल्कि मवेशियों पर भी इसका बहुत गहरा असर डाला है. लाखों की तादात और झुंड की शक्ल में भटकते जानवर तथा चारागाहों में मृत पड़े मवेशियों के अस्थिपंजर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुंदेलखंड सूखे की मार से थक चुका है, टूट चुका है और अब पूरी तरह बिखरने की कगार पर है.■

विदेशों तक गूंजा बुंदेलखंड का सूखा

प्रदेश और केन्द्र सरकारें बुंदेलखंड की बदहाल होती स्थिति से लाख आंखें चुराए, पर इससे हक़ीकत छिपने वाली नहीं. बुंदेलखंड में किस कदर सूखा है और यह क्षेत्र कितना भूखा है इसकी गूंज सात समंदर पार तक पहुंच चुकी है. बीते 11 अप्रैल को खजुराहो से चलकर यहां आईं नीदरलैंड की दो छात्राओं ने जब यहां की स्थिति देखी तो वे भी सन्न रह गईं. मेट और सायने नामक इन छात्राओं ने महोबा जनपद के जैतपुर विकास खंड पहुंचकर थुरट गांव का जायजा लिया. उन्होंने ग्रामीणों से बात की और खाद्य सुरक्षा, सूखा राहत, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आंगनबाड़ी व्यवस्था सहित मनरेगा का सच खंगाला. चौथी दुनिया प्रतिनिधि से हुई बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि बुंदेलखंड के हालात ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से एक रिपोर्ट तैयार कर इस विभीषिका से भारत सरकार को अवगत कराएंगी.■

वाहन धुलाई पर लाखों लीटर पानी स्वाहा

सूखा और पेयजल संकट से निपटने को लेकर बुंदेलखंड का प्रशासनिक तंत्र कितना गंभीर है यह अंदाज़ उन सर्विस स्टेशनों से लगा सकते हैं जो वाहन धुलाई के नाम पर प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं. बुंदेलखंड के सातों जनपदों में करीब एक हजार से भी ज्यादा धुलाई सेंटर आबाद हैं जो सूखे के संकट को और अधिक तल्ख कर रहे हैं. इनके लिए न कोई नियम हैं और न इन पर कोई पाबंदी. इन पर नकेल कसना तो दूर उल्टे जल संस्थान इनको टैंकरों से जल आपूर्ति कर पैसे बटोर रहा है. बताते हैं कि महोबा जनपद में सूखा प्रभावित क्षेत्रों को टैंकर भेजने पर ना नुकुर करने वाले अधिकारी धुलाई संचालकों के एक फोन पर पानी भेज देते हैं हालांकि यह अलग बात है कि इसके एवज़ में उनकी मुट्ठी गर्म की जाती है.■

प्रशासन सुस्त समाजसेवी चुस्त

सूखे से निपटने में भले यहां का प्रशासन सुस्त नज़र आ रहा हो पर बुंदेलखंड में सक्रिय समाजसेवी संस्थाएं और समाजसेवा की मंशा वाले लोग इस समस्या से निपटने जैसे मामले में बेहद गंभीर दिख रहे हैं. महोबा जनपद के खरेला गांव में अपना डीजल और समय खर्च कर रामविहोर उर्फ राजू मिश्रा ने पशुओं के पेयजल की जो व्यवस्था की है वह काबिले तारीफ भी है और प्रशासन के गाल पर एक तमाचा भी. बताते हैं कि इस क्षेत्र के ज्यादातर गांवों में मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं बचा है, जिसके चलते श्री मिश्रा ने अपने एकमात्र कामयाब ट्यूबवेल की मदद से एक बंधी भर दी है जिसमें प्रतिदिन हजारों पशु पानी पी रहे हैं. महोबा जिले में ही आनन्दम नामक संस्था ने जगह-जगह सीमेन्ट की टंकी रखवाकर मवेशियों के पेयजल की व्यवस्था की है.■

पानी व्यापार से जुड़े लोगों की बल्ले-बल्ले

बुंदेलखंड में गहराया पेयजल संकट कुछ लोगों के लिए व्यापार बन गया है. पानी उपलब्ध कराने के नाम पर जबरदस्त जल दोहन किया जा रहा है. पानी को ठंडा कर 50 रुपये प्रति केन की दर से यहां पानी बेचा जा रहा है. जानकार कहते हैं कि समूचे बुंदेलखंड में एक करोड़ रुपये का पानी व्यापार प्रतिमाह हो रहा है. इस कारोबार में कुछ रजिस्टर्ड फर्म हैं तो ज्यादातर इस काम को डग्गामारी के रूप में कर रहे हैं. सरकारी अफसरों और बाबुओं को मुफ्त में पानी पिलाने के कारण इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती.■

सूखे की असल वजह नीतियों में चूक

ललितपुर सिंचाई प्रखंड-द्वितीय के अधिशासी अभियंता के के अग्रवाल स्वीकारते हैं कि बुंदेलखंड के हालात बेहद खराब हो चुके हैं. इनकी मानें तो इस क्षेत्र में गहरा चुके जल संकट से उबरने के लिए सरकार को अपनी नीति में अमूल-चूल परिवर्तन करना होगा. श्री अग्रवाल के मुताबिक लोगों को पानी के उपयोग में सावधानी और दूरदर्शी सोच से काम लेना होगा. गेहूं की फसल में 40 से 50 सेमी पानी खर्च होता है जो यहां के जल भंडारण को निगल रहा है, ऐसे में किसानों को खेती के प्रकार बदलने होंगे. बतौर सुझाव वह दलहन, तिलहन और फलों की खेती करने पर बल देते हैं. उनका मत है कि यदि हम टेक्नोलॉजी की मदद लें और वाटर रीचार्जिंग पर फोकस करें तो बुंदेलखंड को सूखा मुक्त किया जा सकता है. उदाहरण के रूप में वह रबर डैम का नाम लेते हैं. और कहते हैं कि बेमतलब साबित हो रहे स्थाई चेक डैमों की जगह रबर डैम वाटर रिचार्ज करने में अधिक कारगर सिद्ध होंगे. इनसे हुई बातचीत में जो अहम बिन्दु उभर कर सामने आया वह था व्यवस्था को लागू करने में हो रही चूक. जिस प्रकार गैर तकनीकी विभागों को जल संचयन, संवर्धन और संरक्षण का काम सौंपा जा रहा है उससे धन की बर्बादी तो हो रही है पर सकारात्मक परिणाम न निकले हैं और न कभी निकल पाएंगे. बुंदेलखंड की तस्वीर बदलनी है तो तकनीकी जानकार अधिकारियों का चयन कर उन्हें इस काम पर लगाया जाना आवश्यक हो जाता है.■

देश में पानी का भीषण संकट

सूखता भविष्य

फ़ोटो- प्रभात पाण्डेय

सोरिन शर्मा

मध्य प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से में गर्मी प्रारंभ होते ही पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. बुंदेलखंड में सर्वाधिक जल संकट है, जबकि शिवपुरी, बालाघाट, बैतूल और मालवा अंचल के अनेक क्षेत्रों में पानी का परिवहन करना पड़ रहा है. लगभग 30 जिलों में पानी का अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है. बुंदेलखंड की धरती तो लगातार पिछले पांच सालों से सूखे का सामना कर रही है. उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्यप्रदेश की सीमा में आने वाले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, सागर जिलों में पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है. छतरपुर नगर में तीन से चार दिनों में एक बार पानी प्रदाय किया जा रहा है. बोर सूख गए हैं. भूमिगत जल स्तर की स्थिति यह है कि कई जगह पांच सौ फुट गहराई पर भी पानी नहीं मिल रहा है. एक हजार फुट तक के बोर खुदवाए जा रहे हैं, उनमें भी मामूली मात्रा में पानी उपलब्ध हो पा रहा है. आलम यह है कि लोग कई-कई मील पैदल चलकर और पहाड़ चढ़कर पानी लाने को मजबूर हैं. छतरपुर के आसपास सबसे बड़ी समस्या पानी के स्त्रोत की है जो कि दूर एक पहाड़ पर स्थित है. लोग मीलों का सफर तय करने के बाद पानी लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं.

टीमकगढ़ जिले में भी लगातार सूखा पड़ रहा है. खेतों की जमीन तो चटक ही रही है साथ ही पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है. यहां पुलिस की निगरानी में पानी का वितरण किया जा रहा है. नहरों पर प्रशासन को पुलिस का पहरा लगाना पड़ा है, हालांकि कई नहरों में भी पानी खत्म होता जा रहा है. सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है. उपलब्ध पानी को पीने के लिए एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं. पन्ना और दमोह जिले के शहरों में टैंकरों से पानी वितरित किया जा रहा है. यहां भी भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है. दमोह में चार सौ फुट से नीचे के स्रोतों में ही थोड़ा बहुत पानी बचा है. दतिया जिले के अधिकांश गांवों में लोगों को पानी एक से तीन किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है. सागर शहर में प्रतिदिन पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है. यहां का तालाब लगातार सूखता जा रहा है. इस वजह से पेयजल सप्लाई दो से तीन दिन में हो रही है.

डेढ़ किमी से ला रहे पानी

बैतूल जिले की भैंसदेही विधानसभा के धायवानी पंचायत के 900 की आबादी वाले टाकी गांव में पानी का भयंकर संकट है. गांव के दोनों हैंडपंप सूख चुके हैं. क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी सुबह जंगल के बीच से पथरीला रास्ता तय कर पानी का इंतजाम करने निकल जाते हैं. हर घर को बराबर पानी मिलता है. एक समय में एक साथ गांव के हर घर के लोग डेढ़ किमी दूर और 300 मीटर नीचे उतरकर एक नाले में बनी झिरिया (गड्ढे) से पानी भरने पहुंचते हैं. यह झिरिया भी 15 दिन में सूख जाएगी. सरपंच बाबूलाल जावलकर का कहना है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखा है कि गांव में पानी परिवहन किया जाए, परंतु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है. गांव का एकमात्र सहारा वही झिरिया है.

ग्वालियर-चंबल संभाग में भी पानी का संकट गहराता जा रहा है. इस क्षेत्र में सर्वाधित जल संकट का शिकार शिवपुरी शहर है. यहां सालभर से पानी का परिवहन किया जा रहा है. गर्मी में तो हाल यह कि वार्ड में टैंकर के आते ही लोग टूट पड़ते हैं. पांच मिनट के भीतर पूरा टैंकर खाली हो जाता है. यहां पानी की जद्दोजहद में लोगों के बीच न केवल झगड़े हो जाते हैं, बल्कि कई बार लाठी-फरसे तक चल चुके हैं. महाकौशल के बालाघाट नगर में पेयजल की समस्या गहरा गई है. वार्डवासियों ने यहां पेयजल की आपूर्ति कराए जाने की मांग की है. यहां पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है. प्रत्येक वार्ड में एक ही हैंडपंप है, इस वजह से आए दिन पानी को लेकर वार्डवासियों में विवाद होता है.

मालवा-निमाड़ में हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नर्मदा नदी पर बांध बन जाने के कारण जल संकट कुछ कम हुआ है लेकिन इसके बाद भी अनेक क्षेत्र गर्मी का मौसम आते ही जल संकट से जूझने लगे हैं. खंडवा शहर की जल वितरण व्यवस्था तीन बड़े जल स्रोतों पर आश्रित होने के बावजूद शहर में एक दिन के अंतराल में पानी का वितरण हो रहा है. नर्मदा जल वितरण के लिए निगम द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है. निगम ने नर्मदा जल योजना का दायरा तो बढ़ाया लेकिन इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिली है, क्योंकि नर्मदा जल की लाइन का कनेक्शन सुक्ता की लाइन से ही जोड़ा गया है. एक ही मुख्य पाइप लाइन में सुक्ता से जहां 24 लाख गैलन पानी रोज छोड़ा जा रहा है वहीं चारखेड़ा से 10 एमसीएफटी नर्मदा का पानी आ रहा है. इंदौर में भू-जल स्तर गिरने से अप्रैल में ही जलसंकट गंभीर रूप लेता जा रहा है. बीते तीन साल में यह पहला मौका है जब निगम को अप्रैल में पानी के टैंकर दौड़ाने पड़ रहे हैं. फिलहाल शहर के सौ से ज्यादा क्षेत्रों में जलसंकट ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. शहर के 25 प्रतिशत क्षेत्रों में नर्मदा लाइन नहीं है. वहां लोग निजी व सरकारी बोरिंग पर निर्भर हैं. जलस्तर कम होने से बोरिंग सूख रहे हैं या कम पानी दे रहे हैं. वहीं पानी की जरूरत बढ़ रही है. इसे पूरा करने के लिए निगम को सौ से ज्यादा टैंकर भेजने पड़ रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिया 405 करोड़ का राहत पैकेज

सूखे की समस्या से जूझ रहे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के तहत 405 करोड़ रुपये प्रदेश को दे दिए. इसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी. विभागों पर 1 हजार करोड़ रुपये की उधारी चढ़ गई थी, इसे चुकाने के लिए फरवरी में प्रस्ताव भेजकर राशि मांगी गई थी, जिसके मद्देनजर वित्तीय वर्ष समाप्त होने से तीन दिन पहले राशि जारी कर दी गई. इसमें पेयजल का इंतजाम करने के लिए 70 करोड़ रुपये दिए गए हैं. हालांकि, राज्य योजना आयोग ने 210 करोड़ मांगे थे. आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड पैकेज का दूसरा चरण 2016-17 में समाप्त होगा. जल संसाधन, कृषि, सहकारिता, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य विभागों ने दतिया, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और सागर में 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के काम कर दिए, लेकिन राशि का भुगतान नहीं हुआ. राज्य सरकार ने विभागों को देनदारी चुकाने के लिए यह राशि अपने खजाने से दी. इस राशि को हासिल करने के लिए आयोग ने फरवरी में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था.■

पारंपरिक उपायों को भूलने की वजह से सूख रहा है राजस्थान

एक फीसद जल से जी रहा मरु प्रदेश

राजस्थान के बड़े भू-भाग में जल स्तर पिछले 10 वर्षों में 5 से 10 मीटर तक नीचे गया है और कुल 237 ब्लॉकों में से अधिकतर ब्लॉक पानी की उपलब्धता की दृष्टि से डार्क और अति दोहन जोन के रूप में घोषित किए जा चुके हैं. भू-गर्भीय जल का बिना सोचे-समझे और बढ़ता उपयोग चिंता का विषय बन रहा है. पानी की कमी के कारण खेती, काम-धंधे, मजदूरी और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिनके कारण गांवों के लोग पलायन कर शहरों में आने लगे हैं. गांव खाली होते जा रहे हैं.

सुनीता सिंह

राजस्थान स्थाई रूप से पानी की कमी वाला राज्य है. यह और बात है कि यह राज्य अपने जुझारू तेवरों के चलते इस समस्या से निपटने के पारंपरिक साधनों के सहारे पानी की कमी की समस्या से पार पाता रहा है. हालांकि, बदलते दौर में परंपराओं का तेज़ी से हो रहा लोप राज्य के लिए संकट का संकेत भी है. जहां तक पानी की उपलब्धता की बात है तो चम्बल, टिहरी, माही, रावी, व्यास आदि नदियों के पानी के बंटवारे के मामले अभी हल नहीं हुए हैं. देश में उपलब्ध जल का केवल एक प्रतिशत जल ही राज्य में उपलब्ध है. राज्य में होने वाली औसत वर्षा भी लगभग 57.51 सेमी है. चम्बल ही एक ऐसी नदी है, जो मौसमी नहीं है. इसमें पूरे बरस पानी का प्रवाह रहता है.

10 बरस में 5 से 10 मीटर तक नीचे गया जल स्तर

राजस्थान के बड़े भू-भाग में जल स्तर पिछले 10 वर्षों में 5 से 10 मीटर तक नीचे गया है और कुल 237 ब्लॉकों में अधिकतर ब्लॉक पानी की उपलब्धता की दृष्टि से डार्क और अति दोहन जोन के रूप में घोषित किए जा चुके हैं. भू-गर्भीय जल का बिना सोचे-समझे और बढ़ता उपयोग चिंता का विषय बन रहा है. पानी की कमी के कारण खेती, काम-धंधे, मजदूरी और रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिनके कारण गांवों के लोग पलायन कर शहरों में आने लगे हैं. गांव खाली होते जा रहे हैं. राजस्थान में तो हर साल किसी न किसी क्षेत्र में अकाल व सूखे की स्थिति अवश्य पाई जाती है. राजस्थान में पशुओं की संख्या भी अधिक है. लगभग 70 प्रतिशत लोगों का जीवन निर्वाह कृषि व पशुपालन पर निर्भर है.

राजधानी जयपुर का हाल बदहाल

जलस्तर नीचे जाने के कारण पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो रही है. राजधानी जयपुर जैसे शहर में भी कई इलाकों में ट्यूबवेल, हैंडपंप, टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता है. भू-जल दोहन का स्तर लगभग 200 मीटर तक पहुंच गया है. अब तक तो करीब 200 किलोमीटर दूर से आने वाला बीसलपुर बांध का पानी जयपुर की प्यास बुझाता रहा है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या और जलसंकट बढ़ रहा है, उससे कुछ समय पश्चात अकेला बीसलपुर जयपुर की प्यास नहीं बुझा सकेगा.

25 शहर जूझ रहे जल संकट से

जहां तक पूरे राजस्थान की बात है, जल संकट के मामले में राज्य की स्थिति बहुत गंभीर है. राज्य के 25 शहरों में तीन से सात दिन में एक बार पेयजल की आपूर्ति होती है. राजधानी जयपुर के कई इलाकों में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही टैंकरों से पानी की आपूर्ति का प्रबंध करना पड़ता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के गांवों की क्या स्थिति होगी. आजादी के बाद की सरकारों ने विकास का जो मॉडल चुना, उससे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा मिला. भू-जल के अंधाधुंध दोहन की प्रवृत्ति तो बढ़ी ही, नदियों और दूसरे जल स्रोतों को भी दूषित करने का सिलसिला शुरू हो गया. परंपरागत पेयजल स्रोतों की उपेक्षा हुई.

भूलने लगे लोग अपना पारंपरिक हुनर

जो राजस्थान अपनी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों के लिए मशहूर था, वहां के लोग भी अपने इस हुनर को भूलने लगे. नतीजा सामने है. जो तालाब, कुएं, खूबसूरत बावड़ियां और कुंड अपनी शान पर इतराते थे, उन्हें हमने भुतहा बना दिया. हजारों जल स्रोतों को गंदगी से पाट दिया गया. जल स्रोतों के साथ हमने जो दुर्व्यवहार किया, उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं. गांवों में ही नहीं शानदार फ्लैटों में रहने वाले लोग भी पानी के लिए तरस रहे हैं. जल स्रोतों का श्राप असर कर रहा है. लातूर में पैदा हुए विकट हालात के बाद तो हमें संभल जाना चाहिए. जल स्रोतों की सुध लेनी चाहिए. पानी और उसके स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन से लेकर उनके प्रबंधन के प्रति गंभीरता बरतने की आवश्यकता है.

फ़ोटो- प्रभात पाण्डेय

राजस्थान में बारिश का हाल

बारिश के मौसम में बरसे पानी को आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो पूर्वी राजस्थान में जहां सामान्य वर्षा का आंकड़ा साल 2015 के लिए 574.6 मिमी था, वह मानसून की विदाई तक महज 539.7 मिमी रह गया. कुछ ऐसा ही हाल आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान का भी रहता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में पश्चिमी राजस्थान में बारिश का आंकड़ा कुछ सुधरा है, लेकिन वह इतना भी नहीं है कि इससे राजस्थान सूखे की आशंका से निजात पा ले.

अकाल का घर

बाड़मेर जिले के पिछले 100 साल के आंकड़े देखें तो 80 साल सूखे के काले साये में बीते हैं. बाकी बचे 20 सालों में से 10 साल सुकाल और 10 साल 50-50 वाला हिसाब-किताब रहा. यहां पानी की उपलब्धता देखें तो कुल जरूरत का 10 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो पाता, बाकी 90 प्रतिशत की पूर्ति के लिए निजी टांके से 40 प्रतिशत, सरकारी टैंकरों से 10 प्रतिशत और खारे पानी से 20 प्रतिशत तक की भरपाई होती है. फिर भी 30 प्रतिशत का भारी अंतर रहता है, जिसका कोई स्रोत नहीं है. निजी टांके से जिस 40 प्रतिशत पानी की भरपाई होती है, वह भी बरसात के भरोसे हैं. अगर बूंदे न बरसीं तो निजी टांके की भरपाई का प्रतिशत 40 से लुढ़ककर 5 प्रतिशत तक आ जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

देश में पानी का भीषण संकट

सूखता भविष्य

प्रशान्त शरण

रहिम पानी राखिये बिन पानी सब सून रहीम की उक्त उक्ति झारखंड में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है. उत्पन्न गंभीर जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार को पूरे राज्य में आपदा घोषित करनी पड़ी. पूरे राज्य में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तालाब, कुएं और राज्य के लगभग सभी हैंडपम्प सूख चुके हैं. एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को पूरी रात जागना पड़ रहा है, स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि राज्य सरकार को पेयजल एवं सिंचाई विभाग से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करनी पड़ी. शहर में तो कभी-कभी पानी मिल भी जाता है, पर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अत्यंत भयावह है. स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मिल को पानी के अभाव के कारण बंद करना पड़ा. ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करने लगे हैं, पंद्रह सौ फीट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है. खेतों की स्थिति तो और भयावह है पानी के अभाव में खेतों में दरारें पड़ गईं हैं. पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो गया है.

राज्य में लोगों को पानी की कमी की वजह से तड़पता देख झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए अगर सेना की भी मदद लेनी पड़े तो सरकार ले. राज्य में उच्च न्यायालय की फटकार एवं गंभीर जल संकट उत्पन्न होने के बाद राज्य सरकार की नींद खुली. सरकार ने खराब पड़े हैंडपम्पों को ठीक कराने के साथ ही वर्षा के जल संचयन को लेकर एक लाख छोटे तालाब खोदने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जलसंकट से निबटने के लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिया गया है. सरकार अपने टैंकरों के साथ ही किराए पर टैंकर लेकर आम लोगों को पानी मुहैया करा रही है. बड़े कुओं के साथ ही एक लाख छोटे तालाब पूरे राज्य में बनाए जा रहे हैं. किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिए जा रहे हैं. इससे भविष्य में बहुत हद तक जलसंकट से उबरा जा सकता है.

राज्य में जलसंकट आपदा घोषित-चौधरी

झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी का कहना है कि जल संकट से निबटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है. जल संकट को देखते हुए विभाग ने इसे आपदा घोषित किया है और सारे कर्मचारी एवं अधिकारियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है. राज्य में खराब पड़े हैंडपम्पों के मरम्मत का निर्देश दिया गया है, ताकि लोगों को पानी मुहैय्या कराया जा सके. विभाग के टैंकरों के साथ ही किराए पर टैंकर लेकर लोगों को पेयजल मुहैय्या कराया जा रहा है. राज्य में गंभीर जल संकट है. इससे उबरने की तैयारी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष वर्षा बहुत ही कम हुई थी जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. मंत्री ने कहा कि पूरा राज्य गंभीर जलसंकट से गुजर रहा है, लेकिन पलामू प्रमंडल एवं पठारी क्षेत्रों की स्थिति अत्यंत भयावह है. उन्होंने कहा कि राज्य में चालीस हजार हैंडपम्प खराब पड़े हैं. हम इसे गर्मी में ही ठीक कर देना चाहते हैं, नए हैंडपम्प न लगाने पड़ें. इस कार्य के लिए अभियंताओं की टीम को लगाया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे डीप बोरिंग भी गंभीर समस्या पैदा कर रही है, उससे काफी नुकसान हो रहा है. डीप बोरिंग पर रोक लगाई है. इसे रोकने के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं आमजनों को भी आगे आना होगा.

सबसे गंभीर स्थिति पलामू प्रमंडल के साथ ही पठारी क्षेत्रों की है जहां पानी है ही नहीं. इन क्षेत्रों में लगातार सूखा भी पड़ता रहा है. लोगों को स्वच्छ पानी देने का नारा इन क्षेत्रों में महज नारा ही बनकर रह गया है. पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से लोग गड्ढे से कीचड़ को छानकर

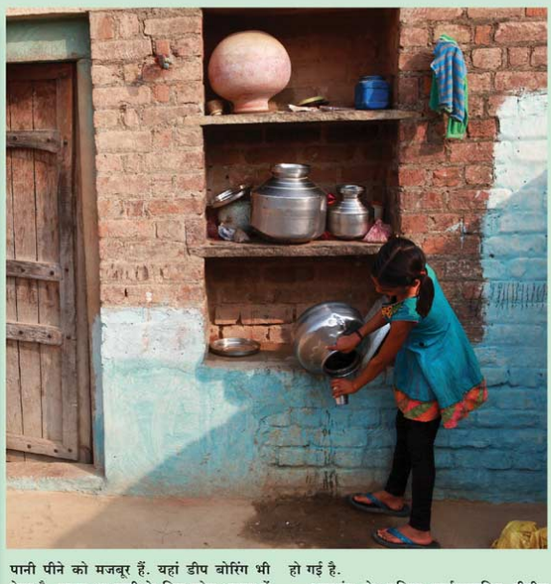

पानी पीने को मजबूर हैं. यहां डीप बोरिंग भी फेल है. चुल्लू भर पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं. नलों पर बंदूकों के साथ पहरेदारी हो रही है. बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है. लोग पानी के अभाव में इन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने लगे हैं.

जलसंकट का असर राज्य में पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ रहा है. सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड-डे-मिल योजना पानी के अभाव के कारण बंद हो गई है. अगर किसी स्कूल में यह योजना चल भी रही है, तो वहां पढ़ने वाले बच्चों से ही दो-दो किलोमीटर से पानी मंगाकर उनके लिए खाना बनाया जा रहा है. पानी के अभाव में सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी कम हो गई है.

झारखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल से घिरा है. फिर भी शुद्ध पानी की मात्रा सीमित है, पानी का दुरुपयोग न हो इस पर गंभीरता से विचार कर ठोस रास्ता निकालना होगा. नहीं तो आने वाले वर्षों में रांची ही नहीं पूरे राज्य में गंभीर जलसंकट उत्पन्न होगा और लोग पानी के लिए पलायन करेंगे. राज्य में इस संकट के लिए राज्य सरकार ने कभी ठोस प्रयास नहीं किए. योजनाएं कागज पर तो बनी पर धरातल पर नहीं उतर सकीं. रुपयों का केवल बंदरबाट हुआ. यह जलसंकट सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है, सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन बिना किसी योजना के. राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दस साल में पेयजल आपूर्ति के लिए लगभग बीस हजार करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, लेकिन जल संकट कम होने की जगह बढ़ता ही गया.

जलापूर्ति के लिए योजना ही गलत बनी और जो पाईपलाइन बिछाई गई वह बेकार साबित हो रही है. अधिकारियों ने केवल जमीन का पानी निकालने का ही काम किया, रिचार्जिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया. कई इलाकों में तो भू-जल स्तर 800 से 1500 फीट नीचे तक पहुंच गया है. यही वजह है कि जल निदेशालय को यह चेतावनी देनी पड़ी कि अगर इसी तरह पानी का दोहन होता रहा, तो दस साल में जमीन के भीतर का पानी खत्म हो जाएगा.

रांची एवं अन्य क्षेत्रों में जलसंकट के लिए अधिकारियों के साथ भूमाफिया भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं केवल रांची में 40 तालाब थे, अब केवल शेष 22 बच गए हैं. शेष बड़े तालाबों को भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बेच डाला और अब तालाबों की जगह आलीशान मकान बन गए हैं. इस शहर से चार बड़ी नदियां गुजरती थीं, पर नदियों का अतिक्रमण कर उनको अब नाला बना दिया गया है. झारखंड में राज्य गठन के समय 75 हजार कुएं थे जो घटकर अब दस हजार रह गए हैं और अब वह भी सूख गए हैं. राज्य में सिंचाई की स्थिति इतनी भयावह है कि पानी के अभाव में खेत सूख गए हैं. पिछली बार कम वर्षा की वजह से अनाज की पैदावार मात्र तीस प्रतिशत हुई थी. इस बार भी उम्मीद कम ही दिखाई पड़ रही है. सिंचाई की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने दो हजार से भी अधिक चेकडैम बनाए पर इसमें पानी ही नहीं है. वह बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है. अगर अब भी हम नहीं चेते और सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए ठोस नीति नहीं बनाती है और उसका पालन कड़ाई से नहीं कराती है, तो आने वाले दिनों में पानी के लिए ही खून-खराबा होगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

जल बिना मुश्किल में जीवन

सरोज सिंह

पिछले दो सालों से सूखे की मार झेल रहे बिहार को इस साल भी राहत नहीं मिली और सूबे के लगभग आधे से अधिक जिले पानी के बिना बिलबिला रहे हैं. किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है और बर्बाद होती फसलों को देखकर उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं. मार्च के महीने में ही जलस्तर दो फीट नीचे चला गया और मई-जून महीने में इसके पांच फीट नीचे जाने की आशंका है. इसका नतीजा यह है कि पानी के बिना अब लोग बिलबिलाने लगे हैं. किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं. हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सूखा व जल संकट से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को परेशानी न हो. सूखे और जल संकट की भयावहता पर नज़र डालें तो लगता है कि शाहाबाद का इलाका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है.

शाहाबाद की धरती इस समय पानी के सवाल पर बेपानी हुए जा रही है. कहीं पीने के पानी से जुड़े सवाल, तो कहीं खेतों के पानी से जुड़े सवाल आम लोगों के हलक सूखा रहे हैं. इस भूखंड के चार में से दो जिले तपती हुई कैमूर पहाड़ी से बरस रहे आग के गोले और नीचे गए जल स्तर के बीच झुलस-झुलसकर स्याह हुए हैं, तो दो जिले खेतों के पानी के सवाल पर अपनी रंगत उड़ाए बैठे हैं. कैमूर और रोहतास में कैमूर पहाड़ी का प्रभाव है तो गंगा के किनारे स्थित भोजपुर के साथ बक्सर का संपूर्ण दियरांचल खेती के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रहा है. यहां का आर्सेनिक युक्त पानी पहले से ही आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या है. ऊपर से खेतों में खड़ी रबी(गरमा) की फसल को अब पानी नहीं मिलेगा. इसकी संभावना प्रबल हो उठी है. शाहाबाद प्रक्षेत्र के कैमूरांचल और दियारांचल प्रक्षेत्रों की समस्या एक ही है. कहीं पीने का पानी तो कहीं खेतों का पानी समस्या बना हुआ है. दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस समस्या का सीधा प्रभाव आम जन और जीव जंतुओं पर पड़ता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में कैमूर की पहाड़ी पर भीषण गर्मी और पानी की कमी की वजह से पांच हजार पालतू पशुओं की जान गई थी. इसके बाद भले ही इतने बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं या वन्य प्राणियों की भीषण गर्मी और पेयजल के अभाव में जान नहीं गई लेकिन इनका पलायन जरूर हुआ है. इन पशुओं का पलायन समीप के झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में हुआ था जो कि अब भी जारी है. कैमूर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से लेकर तलहटी के बीच 139 गांव बसे हैं. जिनका जीवन पहाड़ी झरनों पर आधारित है. ये झरने पिछले कई वर्षों से मार्च महीने के आते-आते सूख जाते हैं. जिसका सीधा असर यहां

पानी की उपलब्धता पर पड़ता है. इन झरनों से निकला पानी रोहतास और कैमूर के बदुनाथपुर से लेकर अधौरा तक के वन्य प्राणियों, पालतू पशुओं और आम लोगों के लिए सदैव जीवनदायी रहा है. हाल के दशकों में इन झरनों से पानी नहीं निकलना कैमूरांचल के लिए बुरे संकेत हैं.

इस बार भी यही हाल है. सिर्फ दुर्गावती नदी ही एकमात्र जल स्त्रोत है. जो अभी लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराती है. इस वर्ष इस क्षेत्र में लगभग सत्रह हजार हेक्टेयर ज़मीन पर लगी रबी की फसल पानी के आभाव में पूरी तरह बर्बाद हो गई है. प्रति हेक्टेयर अनाज की उपज दो क्विंटल कम हुई है. उधर दियरांचल की बात करें तो भोजपुर और बक्सर जिले में गंगा के झाइल से लेकर ऊपरी हिस्से तक आर्सेनिक युक्त पानी पीकर हर साल हजारों लोग अस्तपालों तक पहुंच रहे हैं. यहां का जलस्तर औसतन चार मीटर नीचे खिसक गया है. जिसके कारण पहले से लगाए गए चापाकल और नलके जबाव दे चुके हैं. अलबत्ता गंगा में मिलने वाली कुछ सहायक नदियों का जल किसानों के लिए डूबते को तिनके का सहारा मिलने जैसा है. परंतु यह लाभ सिर्फ बीस प्रतिशत लोगों को ही मिल पाता है. एक तरफ सोन नहरों के अंतिम छोर पर पर बसे इस क्षेत्र को नहरों का लाभ तो मिलता नहीं है वहीं दूसरी तरफ गंगा की धारा के लगातार बदलने और खिसकने की वजह से जलस्तर में काफी गिरावट आई है. हाल ही में सासाराम में आयोजित जल सम्मेलन में पहुंचे देश के पानी विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने कहा था कि यदि शाहाबाद की जल समस्या का समाधान समय से नहीं हुआ तो यहां की कृषि को बचाना तो दूर की बात है विषम भागौलिक परिस्थितियों वाले इस क्षेत्र में सबको पानी दे पाना भी कठिन हो जाएगा. उन्होंने कैमूर पहाड़ी पर बांध बनाने और दियरांचल में छोटी-छोटी नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाने का सुझाव दिया था. पानी से जुड़े आंदोलन की अगुआई कर रहे समाजवादी नेता राम बिहारी सिंह ने बताया कि शाहाबाद में पानी बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में उभरेगा. उन्होंने कैमूर पहाड़ी की तलहटी में कदवन परियोजना, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, पहाड़ी पर महादेवा परियोजना, मैदानी भाग में मलई बैराज परियोजना और चौंसा लिफ्ट कैनाल परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से मांग की. गौरतलब हो कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में अधूरी पड़ी छह सिंचाई परियोजनाओं में से 40 वर्षों में सिर्फ एक (दुर्गावती जलाशय परियोजना) पूरी हो पाई है. बाकी पांच परियोजनाओं में अभी भी अस्सी प्रतिशत से ज्यादा काम होना बाकी है. अब देखना यह है कि वर्ष 2016 में पड़ने वाली भीषण गर्मी के प्रकोप का सामना यहां के चारों जिला प्रशासन कैसे करते हैं.

कैमूर पहाड़ी पर बसे तीस हजार से ज्यादा वनवासियों के सामने अभी से ही भीषण पेयजल संकट खड़ा हो गया है. निचले हिस्से के चेनारी, सासाराम, शिवसागर और तिलौथू प्रखंडो में लगभग दो लाख लोग पेयजल के लिए सुबह से ही इंतजाम में लग जाते हैं. कैमूर जिले में पूरा अधौरा प्रखंड, चांद, चैनपुर, भगवानपुर और रामपुर के आधे हिस्से घोर पेयजल संकट में हैं. बक्सर का इटाढ़ी, सेमरी, नया भोजपुर, आरा का बहहरा, शाहपुर सहित आधा दर्जन प्रखंड दियरांचल में पेयजल संकट झेल रहे हैं. बीच का हिस्सा सिंचाई छाया क्षेत्र बना हुआ है. जहां के खेतों को पिछले कई वर्षों से पानी नहीं मिला है.

इसी तरह इस साल मगध प्रमंडल में भी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. गौरतलब है कि मगध प्रमंडल के पांच जिलों की अधिकांश खेती वर्षा के पानी पर निर्भर रहती है. आज भी कमोबेश यही स्थिति है. पिछले दो सालों से बेहद कम वर्षा होने की वजह से यहां के किसानों को भारी निराशा हुई. इस साल अब तक जो हालात हैं उससे किसानों के दमफूल रहे हैं. नवादा, जहानाबाद और गया जिले के अधिकतर किसान पूरी तरह अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर हैं. इन क्षेत्रों में कुछ सिंचाई परियोजनाएं वा पुरानी नहरें हैं भी तो वे अपना अस्तित्व को खो चुकी हैं. इनके जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना सरकार की ओर से नहीं चलाई जा रही है. जहानाबाद में खेतों की सिंचाई के लिए कोई नहर, तालाब वा बड़ा आहर नहीं है. जिसके कारण यहां के किसानों को अपनी फसल के लिए वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है.

सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि सूखे पर सरकार की पूरी नज़र है और किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने नहीं दी जाएगी. सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बार अच्छे मानसून के आसार हैं इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन भाजपा नेता सुशील मोदी कहते हैं कि सरकार को किसानों और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है. आधे से अधिक सूबा सूखे की चपेट में है और सरकार सोई हुई है. लगता है वह भगवान भरोसे है और बारिश का इंतजार कर रही है लेकिन तब तक तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा. उधर लालू प्रसाद ने भी जल संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राजद कार्यकर्ताओं को इस बारे में पार्टी को जल्द से जल्द अवगत कराना चाहिए ताकि उस फीडबैक के आधार पर सरकार को समस्या के समाधान के लिए कहा जा सके. साफ है कि सूखे के नाम पर राज्य में राजनीति हो रही है क्योंकि जिसकी सूबे में सरकार है वह कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांग रहा है. बहरहाल इस राजनीति में सूबे की जनता पिस रही है और आधे बिहार में पानी के लिए हाहाकार मचा है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

हमें पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, उन्हें ऊपर उठाने, पर्याप्त व उचित शिक्षा देने व समाज में सम्मान दिलाने के लिए कदम उठाने होंगे. रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बिल्कुल अलग मामला है, जिस पर केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई. मैं उसकी मां के बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय से बिलकुल हैरान नहीं हूं. एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं. यह सरकार हिंदुत्व का अलमबरदार होने में गर्व महसूस करती है. आरएसएस उनका समर्थन कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद उनका समर्थन कर रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू समाज के भीतर बहुत सारी कुरीतियां है.

उम्मीद करिए कि एक बेहतर मानसून आए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को आदेश दिया है कि वह महाराष्ट्र में खेले जाने वाले आईपीएल मैचों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दे. मीडिया में महाराष्ट्र में मैच कराने की भी आलोचना हो रही और हाईकोर्ट द्वारा मैचों के स्थानांतरण के फैसले की भी खूब आलोचना हो रही है. लेकिन, सच्चाई यह है कि देश में फिलहाल गंभीर जल संकट बना हुआ है. महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित है. यह इस हिसाब-किताब का समय नहीं है कि मैचों के आयोजन में कितना पानी खर्च होगा या मैच न कराने से पानी की कितनी बचत होगी. मुद्दा सांकेतिक है. यह ताकतवर और अमीर लोगों का एक भद्दा प्रदर्शन है. जैसे, उन्हें गरीबों की त्रासदी और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है. हाईकोर्ट ने आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है. इस फैसले पर यह सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि ऐसा करने से पानी की बचत होगी या नहीं होगी. दरअसल, यह पानी की मात्रा का सवाल नहीं है और सवाल यह भी नहीं है कि वह पानी लोगों के काम का है या नहीं. यह सवाल है सही और भद्र व्यवहार का.

मुझे लगता है कि बीसीसीआई को खुद ही जगह बदलने का प्रस्ताव देना चाहिए था. ऐसा करने के बजाए बीसीसीआई के सचिव ने एक सार्वजनिक बयान दिया. जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना होगा क्योंकि यदि मैच दूसरी जगह चले जाते हैं तो महाराष्ट्र सरकार को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान होगा. यह बहुत ही घटिया बयान है. बीसीसीआई जितनी जल्दी इस संबंध में सबक सीखेगी क्रिकेट के लिए उतना ही बेहतर होगा. पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लेकर सख्त टिप्पणी की है. बीसीसीआई को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए क्योंकि अहंकार लोकतंत्र में कहीं भी फिट नहीं बैठता.

> महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र सूखे से बुरी तरह प्रभावित है. यह इस हिसाब-किताब का समय नहीं है कि मैचों के आयोजन में कितना पानी खर्च होगा या मैच न कराने से पानी की कितनी बचत होगी. मुद्दा सांकेतिक है. यह ताकतवर और अमीर लोगों का एक भद्दा प्रदर्शन है. जैसे, उन्हें गरीबों की त्रासदी और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है. हाईकोर्ट ने आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है.

दूसरी खबर रोहित वेमुला की मां और भाई द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की है. यह एक ऐसा काम है जिसे अंबेडकर ने बहुत पहले किया था. अगर, हम हिंदू अपने अलग-अलग जातियों के भाईयों के साथ बेहतर बर्ताव नहीं करेंगे तो वे यही रास्ता अपनाएंगे. उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हम उनसे बेहतर बर्ताव करने लगेंगे क्योंकि वह दूसरा धर्म है. हिंदू समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए. हमें पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, उन्हें ऊपर उठाने, पर्याप्त व उचित शिक्षा देने व समाज में सम्मान दिलाने के लिए कदम उठाने होंगे. रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला बिल्कुल अलग मामला है, जिस पर केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई. मैं उसकी मां के बौद्ध धर्म अपनाने के निर्णय से हैरान नहीं हूं. एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि हम हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं. यह सरकार हिंदुत्व का अलमबरदार होने में गर्व महसूस करती है. आरएसएस उनका समर्थन कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद उनका समर्थन कर रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू समाज के भीतर बहुत सारी कुरीतियां है. उदाहरण के लिए छुआछूत, छोटी जाति के लोगों द्वारा ऐसे काम करना जिन्हें कोई नहीं करना चाहता, दहेज प्रथा आदि. हिंदू समाज में कम आमदनी वाले व्यक्ति समस्याओं से अधिक परेशान हैं. भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संस्थाओं के लिए मुसलमानों और ईसाईयों की अनदेखी करने की बात तो समझ में आती है लेकिन उनका रचनात्मक योगदान तब माना जाएगा जब वे हिंदू समाज के लिए काम करें, जिसकी फिलहाल सख्त जरूरत है. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस पर गौर करेगी.

जैसा कि हमने पहले पानी के बारे में बात की, जल आयोग ने माना है कि देश में गंभीर जल संकट है. अगले दो महीने, जब तक मानसून नहीं आ जाता, बहुत कठिन हैं. लेकिन, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि हम यह आशा करें कि इस वर्ष बेहतर मानसून आएगा. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक तरीके से काम करेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

प्यारा कौन, कॉरपोरेट या कृषि जगत

कृषि और किसान से संबंधित संपादकीय (22-28 फरवरी 2016) में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा से उत्पन्न भविष्य के संभावित खतरों की चेतावनी और संकेत, बेबाक तथा सामयिक हैं. भारत की दो तिहाई जनसंख्या कृषि-जगत पर निर्भर है. किसान तथा खेत-मजदूर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों रूपों में शोषण का शिकार हो रहे हैं. किसान अपनी उपज बिचौलियों के हाथों औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं. कृषि उनके लिए अलाभकारी व्यवसाय सिद्ध हो रही है. बैंकों के 1.14 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज को औद्योगिक घरानों के हित में माफ कर दिया गया. सरकार के इस निर्णय से उसकी कृषि क्षेत्र के प्रति उदासीनता व बदनीयती साफ झलकती है. केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना ही चाहिए कि वह भविष्य में कॉरपोरेट जगत के हितों को संरक्षण देगी या कृषि क्षेत्र पर निर्भर बहुसंख्य आबादी के हितों को?

–सत्येंद्र कुमार दुबे, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

लोक पर हावी तंत्र

संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में हाशिमपुरा और मलियाना हत्याकांड के बहाने न्याय व्यवस्था पर उठते ज्वलंत प्रश्नों को रेखांकित किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिसके पास पैसा है उसे ही न्याय पाने का अधिकार है. आज लोक पर तंत्र हावी है जबकि हम लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते. अत: वंचित वर्ग के लिए भी न्याय पाने की त्वरित व्यवस्था हो, जिससे सबूतों को नष्ट होने का मौका न मिले, क्योंकि देर मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आ जाता है.

–सत्य प्रकाश शिक्षक, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

किसानों की आत्महत्या सोच का विषय है

चौथी दुनिया की कवर स्टोरी- मृत्युप्रदेश (28-03 अप्रैल 2016) पढ़ी. इस लेख ने अंदर तक हिला कर रख दिया. इस लेख के हर अल्फ़ाज़ में किसानों का दर्द नज़र आ रहा था और हर अल्फ़ाज़ अपना दर्द बयां करते-करते आंखे भी नम कर गया. आज किसानों की आत्महत्या एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है. पर अब तक हम इसका समाधान तलाशने में असफल क्यों हैं. देश बदल रहा है, पर किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है. आखिर क्यों किसानों की आत्महत्या के बाद ही इस देश की सरकारें जगाती हैं? आखिर क्यों किसानों की समस्याओं का समाधान तलाश नहीं किया जाता? आखिर कब तक देश का किसान खुदकुशी करता रहेगा और सरकारें अपनी सियासत और छवि चमकाने के लिए मुआवजा पर मुआवजा बांटती रहेंगी? यह एक चिंता का विषय है और वक्त रहते सरकारों को इसका समाधान तलाशना होगा. सिर्फ इनके हित में नारे लगाने से कुछ नहीं होगा. बल्कि किसानों के लिए अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे देश का किसान भी गर्व से कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा.

–शाहरुख़ उस्मान देहलवी, *दिल्ली.*

शोषण के शिकार

स्टोरी-इस कलंक से मुक्ति के लिए सिर्फ क़ानून काफी नहीं (अंक 11, 17 अप्रैल 2016) पढ़ा. लेख ने बेहद प्रभावित किया. इस ख़बर ने मुझे सोचने पर मज़बूर कर दिया कि किस तरह से हाथ से मैला उठाने, उसे सिर पर ढोने या मैनुअल स्केवेंजिंग का घिनौना और अमानवीय कार्य आज भी हमारे देश में जारी है. समस्या यह है कि इस प्रथा से जुड़े ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक उनके साथ शोषण होता आया है. यह कार्य उन्हें अनुसूचित जातियों में भी सबसे निचले पायदान पर खड़ा कर देता है. सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए. आज डिजिटल युग में भी यह काम हाथों से करना पड़ रहा है तो सबके लिए शर्म की बात है.

–प्रदीप यादव, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

सभी पार्टियां एक जैसी हैं

कवर स्टोरी-विहिप के झंडाबरदार हैं रूंगटा (17 अप्रैल, 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. प्रभात रंजन दीन ने अपने आलेख के जरिए बहुत सी सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज तक किसी अखबार में पढ़ने को नहीं मिलीं. चौथी दुनिया अख़बार ने ही सबसे पहले कोयला घोटाला उजागर किया था. इस ख़बर को पढ़कर बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त हुईं. कोयला खान आवंटन घोटाला संप्रग सरकार के कार्यकाल में उजागर हुआ, लेकिन सजा भाजपा और आरएसएस से जुड़े उद्योगपतियों को मिली. इससे यह पता चलता है कि सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. कोई पार्टी देश के बारे में नहीं सोचती. सबको केवल अपनी जेब भरने से केवल मतलब है.

– राकेश कुमार मौर्य, *मुंगेर, बिहार.*

गरीबों को मुफ्त रसोई गैस

मोदी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पांच करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर अत्यंत सराहनीय कार्य किया है. मोदी सरकार का यह निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी व देश की करोड़ों महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी लकड़ी या कंडे वाले चूल्हे फूंकते और इससे निकलने वाले धुएं की वजह से आंसू बहाते हुए बिताई है. उज्जवला योजना की वजह से यकीनन इन महिलाओं का जीवन उज्जवल होगा.

–राज किशोर प्रहरी, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

यह कैसी राजनीति है

बाबा साहेब अंबेडकर को सभी राजनीतिक दल अपनाने में लगे हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते को कोई राजनीतिक दल अपनाने को तैयार नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने की और दलित, शोषित एवं वंचितों के बारे में कार्य करने की बात करते हैं. सभी विपक्षी पार्टियां मोदी के इस विचार को दिखावा कहती हैं और राजनीति करने का आरोप लगाती हैं. कांग्रेस ने तो देश में सबसे अधिक राज किया है, लेकिन वह केवल इतना बताए कि उसने अपने दस साल के कार्यकाल में दलितों के लिए क्या किया? मायावती कहती हैं कि वह दलितों की सबसे ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हुआ. राजनीतिक पार्टियां केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने का कार्य कर रही हैं. राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाए के बजाए दलितों के लिए कार्य करने की जरूरत है. क्योंकि देश में आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है जो सोचने पर मजबूर करती है.

–हिमांशु तिवारी, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा

शफीक आलम ने अपने आलेख में देश में जारी जिस अमानवीय प्रथा का जिक्र किया है, वह बेहद अमानवीय है. 21वीं शताब्दी में यह सोचकर रूह कांप जाती है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मल साफ कर रहा है. यह निश्चित तौर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती है कि वो इस अमानवीय प्रथा को खत्म कराए, इससे जुड़े लोगों का पुनर्वास की योजना बनाए ताकि भारतीय समाज के माथे से यह कलंक हट सके. स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी यह एक चुनौती ही है. सरकार को विचार करने की जरूरत है कि आज इस वैज्ञानिक युग में कैसे इस तरह हाथ से मल साफ करने की प्रथा को समाप्त करने की योजना बनाई जा सके.

– सुरेश राम, *गोपालगंज, बिहार.*

काश आज चंद्रशेखर होते

अपने संपादकीय में संतोष भारतीय ने सही ही लिखा कि आज जो आर्थिक नीति अपनाई गई है वह कैसे इस देश के 70 फीसदी लोगों के अनुकूल नहीं है. आज जिस तरह से खेती, मंहगाई, सरकारी पैसे की लूट जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं और जिसका निराकरण होता नहीं दिख रहा है. ऐसे हालात में अगर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होते तो क्या सोचते और क्या करते. युवा तुर्क के तौर पर मशहूर स्वर्गीय चंद्रशेखर होते, तो निश्चित तौर जनता की लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक लड़ते. भारतीय समाज, भारतीय राजनीति को आज चंद्रशेखर की कमी खल रही है, क्योंकि मौजूदा दौर में उनके जैसा कोई नेता हमारे बीच नहीं है.■

–अभिराम सिंह, *सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी! अभी भी चेत जाने का वक्त है

आने वाले दिन या महीने देश के लोगों की जान पर आने वाले संकट के दिन होंगे. लोग चिंतित और परेशान हैं, क्योंकि सूखे की आशंका सारे देश में सामने दिखाई दे रही है. पानी की कमी का ख़तरा सामने दिखाई दे रहा है. और जब मैं लोग कहता हूं तो उसका मतलब गांव में रहने वाले और विशेषकर किसान ज्यादा है, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं, उन लोगों का जिम्मा सरकारें अपने ऊपर मानती हैं. गांव में रहने वालों का जिम्मा नहीं मानती हैं. लातूर में पानी से भरी ट्रेन 5 लाख लीटर पानी लेकर गई, लेकिन वह पानी सिर्फ शहरों में बट रहा है. गांव की किसी को चिंता नहीं है, हो भी नहीं सकती, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब करने का वक्त होता है, तब सरकारें मौज-मस्ती में और काम को मजाक समझकर अपना वक्त टालती हैं. सरकार के पास तंत्र है, सरकार के पास विज्ञान है, सरकार के पास लोग हैं जो यह बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा. पर हमारा मौसम विभाग भी कमाल का है, वह जो भविष्यवाणी करता है, उससे उल्टा होता है. जबकि वहीं बीबीसी की भविष्यवाणी लगभग 90 प्रतिशत सही उतरती है और हमारे देश के लोग बीबीसी की भविष्यवाणी के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं. हमारे मौसम विभाग ने पहले यह कहा कि इस बार पानी कम बरसेगा और पानी का बड़ा संकट आने वाला है. लेकिन अचानक पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सरकार यह प्रचार कर रही है कि मौसम विभाग कह रहा है कि इस बार सामान्य से अच्छी बारिश होगी. इसका मतलब सरकार यह सूचना इसलिए फैला रही है क्योंकि लोगों में पैनिक न हो. पर सरकार यह नहीं समझ रही है कि जब प्यास से और सूखे से लोग मरेंगे, तब क्या हाल होगा?

नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इस आशा में वोट दिया था कि वह उस ढर्रे पर नहीं चलेंगे जिस ढर्रे पर मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी. लेकिन दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी उससे ज्यादा ख़राब ढर्रे पर चल रहे हैं. दो साल बीत गए. लेकिन पानी या सूखे को लेकर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट (आपदा प्रबंधन) का प्लान सामने नहीं आया. आप लोगों को अपने साथ लीजिए और उनसे कहिए कि यह प्रकृति आपदा आने वाली है. आप इस-इस तरह से इसका सामना कर सकते हैं. पर लोगों को धोखे में रखकर अचानक आपदा को आने देना और लोगों को उसमें फंसते हुए देखकर खुद देश या विदेश के फाइव स्टार होटलों में घूमते हुए खाना खाना और अपने सारे वर्ग को जो शहरों में रहते हैं, जिस वर्ग से सत्ता में हिस्सेदारी करने वाले लोग आते हैं. उन लोगों को रिलीफ या मदद मुहैया कराना क्या यह न्याय है? इससे देश के लोगों का जो विश्वास टूटेगा उस विश्वास के टूटने का क्या परिणाम होगा? क्या सरकारों को इसका अंदाजा है?

मैं देश के समझदार पाठकों और सरकार के संवेदनशील अंगों को यह ख़बर देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों मैं बुंदेलखंड की तरफ था. वहां बहुत सारे गांव के लोगों से मेरी मुलाकात हुई. उन लोगों ने एक बात बहुत स्पष्ट मुझसे कही कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो बुंदेलखंड से गुजरने वाली हर ट्रेन लूटी जाएगी. जब उन्होंने यह कहा, तो मैं उनका चेहरा देख रहा था और उसमें यह दृढ़ निश्चय था कि चाहे वह आदिवासी हों, गरीब हों, वंचित हों, उच्च जाति के हों लेकिन गरीब हों. वे यह योजना बनाए बैठे हैं कि वहां से गुजरने वाली ट्रेनें जरूर लूटी जाएंगी. अगर इस बार बारिश नहीं होती है तो कोई भी सरकारी मशीनरी, लॉ एनफोर्समेंट एंजेसी इसे नहीं रोक पाएगी. अगर यह बुंदेलखंड में होगा, तो मुझे डर है यह देश के बहुत सारे हिस्सों में दोहराया जा सकता है.

और जो दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती. हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट चिंतित हैं कि देश में पानी नहीं है. हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट चिंतित हैं कि देश में अनाज नहीं है, सूखा पड़ने वाला है. लेकिन सरकारें चिंतित क्यों नहीं हैं? सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की. अगर आपको किसी भी सरकार की चिंता समझ में आए, तो मुझे एक खत डाल दीजिए कि आपको इतने दिनों में जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं आपको सरकार की चिंता नज़र आई. महाराष्ट्र हाईकोर्ट मुंबई में होने वाले आईपीएल मैचों में कितना पानी खर्च होता है, कितना पानी रोज मुंबई के लिए है, पीने के लिए मिल रहा है या मैदान को ठीक करने के लिए, इसके बारे में सवाल पूछता है, चिंता दिखाता है और यह फैसला करता है कि एक मैच के अलावा और कोई मैच मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कहीं नहीं होगा. मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर मैच होंगे. 30 अप्रैल के अलावा आईपीएल का कोई मैच महाराष्ट्र में नहीं होगा. देश का सुप्रीमकोर्ट चिंता दिखाता है, सरकार से पूछता है कि उसने क्या व्यवस्था की? लोगों को सूखे से बचाने की उसके पास कोई योजना है या नहीं? सरकार ने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सुप्रीमकोर्ट को कोई योजना नहीं दी. ऐसा क्यों है? सरकारें क्यों असंवेदनहीन हो गई हैं लोगों की चिंता से, खासकर गांव के लोगों की चिंता से सरकारें क्यों परेशान नहीं होती हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि इस देश में सरकारें अगर इसी तरह व्यवहार करेंगी, तो अराजकता को बढ़ावा मिलेगा.

सरकारों के काम करने का वक्त और मैं यहां पर मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई फर्क नहीं कर रहा हूं. लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इस आशा में वोट दिया था कि वह उस ढर्रे पर नहीं चलेंगे जिस ढर्रे पर मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी. लेकिन दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी उससे ज्यादा ख़राब ढर्रे पर चल रहे हैं. दो साल बीत गए. लेकिन पानी या सूखे को लेकर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट (आपदा प्रबंधन) का प्लान सामने नहीं आया. आप लोगों को अपने साथ लीजिए और उनसे कहिए कि यह प्रकृति आपदा आने वाली है. आप इस-इस तरह से इसका सामना कर सकते हैं. पर लोगों को धोखे में रखकर अचानक आपदा को आने देना और लोगों को उसमें फंसते हुए देखकर खुद देश या विदेश के फाइव स्टार होटलों में घूमते हुए खाना खाना और अपने सारे वर्ग को जो शहरों में रहते हैं, जिस वर्ग से सत्ता में हिस्सेदारी करने वाले लोग आते हैं. उन लोगों को रिलीफ या मदद मुहैया कराना क्या यह न्याय है? इससे देश के लोगों का जो विश्वास टूटेगा उस विश्वास के टूटने का क्या परिणाम होगा? क्या सरकारों को इसका अंदाजा है?

हम सिर्फ इतना कह सकते हैं और यह निवेदन करना भी चाहते हैं कि अपने इस काहिली और आलसीपन से बाहर निकलिए. देश के लोगों को आने वाली दैवीय आपदा या मानवीय काहिली से पैदा की गई आपदा के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए और उनका साथ लेकर इसका सामना करने की कोशिश कीजिए. आने वाले दिन जो मई महीने से शुरू होंगे, उनमें पानी के लिए इस देश में दंगे होंगे. गांवों में लोग कुएं से पानी नहीं लेने देंगे और लोग हिंसा करके पानी लेंगे, क्योंकि बिना पानी पिए, प्यास की वजह से होने वाली मौत बहुत ख़तरनाक होती है. अनाज़ न मिले तो आदमी तीन-चार दिन गुजार सकता है और तब तक कहीं से घास, कहीं से भीख, कहीं से रिलीफ आदमी को मिल सकता है. बहुत सारी जगहों पर तो इसका भी कोई दूर-दूर तक कोई आसरा नहीं दिखाई देता. लेकिन बिना पानी के कोई मरे या न मरे, गरीब तो मर ही जाएगा और इस देश में 70 प्रतिशत गरीब हैं. इसलिए मेरा अनुरोध है अभी भी वक्त है, लोगों से बात कीजिए. सारे साधु-संतों से कहिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कहिए, सारे एनजीओ से कहिए कि यह आने वाला ख़तरा है. इसका सामना करना पड़ेगा और इस तरीके से किया जा सकता है. क्या सरकार यह रोल नहीं निभा सकती? अगर नहीं निभाती है प्रधानमंत्री जी, तो फिर मेरे पास आपके लिए रोने के सिवाए और कोई चारा नहीं है.■

editor@chauthiduniya.com

असम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं

मेघनाद देसाई

हम 2016 के चुनाव चक्र की शुरुआत में खड़े हैं. पिछला साल नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले दिल्ली में भाजपा की शर्मनाक हार हुई, उसके बाद लालू यादव और नितीश कुमार ने उन्हें बिहार में पटखनी दी. लेकिन यह वर्ष सत्ताधारी दल के लिए अंतराल का वर्ष है. क्योंकि जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से किसी भी राज्य में भाजपा की कोई खास उपस्थिति नहीं है. दरअसल, मोदी के नेतृत्व में सत्ता पर विराजमान होने के कारण भाजपा हर राजनीतिक बहस पर हावी है. इन पांच राज्यों में पार्टी की बड़ी उपस्थिति नहीं होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा कहीं भी दांव पर नहीं लगी हुई है.

तमिलनाडु के चुनावी नतीजों पर राष्ट्रीय दलों का प्रभाव कम रहता है. यह लगभग एक ऑटोनॉमस राज्य है जहां एक ही खोत से पैदा हुई दो पार्टियों ने राज्य पर अपना एकाधिकार जमा रखा है, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता. यहां पेरियार के उत्तराधिकारी सदा जारी रहने वाला महाभारत लड़ते रहेंगे.

पश्चिम बंगाल में किसी गैर-बंगाली पार्टी के लिए घुसपैठ करना उचित नहीं है. वामपंथ जिसने दशकों तक बंगाल पर शासन किया और बर्बाद किया, इस बार ममता बनर्जी से हारने के लिए मुक़ाबला करेगा. और इस मुक़ाबले में अपने साथ कांग्रेस को भी रखेगा. गौरतलब है कि जब वामदल यहां सत्ता में थे तो कांग्रेस ने राज्य की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया. तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस की बंगाल इकाई है जो अपनी तरह की गड़बड़ी फैलाएगी लेकिन फिलहाल बंगाल में इसकी पकड़ मज़बूत है.

केरल में कांग्रेस का मुक़ाबला अपने पुराने सहयोगी से है. दोनों पक्षों में विभाजन हुआ है और दोनों पर धांधली के आरोप हैं. लेकिन इस बार यहां वाम मोर्चे की बारी है. जहां तक शासन व्यवस्था की बात है तो किसी को कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा.

इन तीनों राज्यों में भाजपा की उपस्थति कम रहेगी. एायद उसका खाता खुल जाए लेकिन किसी भी स्थिति में आंकड़ा दोहरे अंकों तक नहीं जाएगा. असम एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा के लिए उम्मीदें हैं. तरुण गोगोई चौथी बार सत्ता के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि अद्वितीय है, लेकिन इसके लिए उन्हें इस बार कड़ा मुक़ाबला करना पड़ रहा है. दरअसल इस वर्ष के चुनावों में वे कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद हैं. इसके बावजूद उनके लिए संकेत अच्छे नहीं हैं. ऐसा लगता है उनकी चौथी जीत तय नहीं है.

शहरों में रहने वाले बुद्धिजीवियों की ज़मीनी रिपोर्टिंग यह बताती है कि इस बार असम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं. हो सकता है कि कांग्रेस न केवल बहुमत हासिल करने में असफल हो जाए बल्कि वह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी न बन पाए. इससे भी बढ़कर हैरान करने वाली बात यह है कि असम में भाजपा न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बल्कि वह अपने दम पर बहुमत भी हासिल कर सकती है या फिर उसे गठबंधन सरकार बनाने योग्य सीटें मिल सकती हैं. यदि ऐसा नतीजा आ गया तो यह 2014 के लोकसभा चुनावों से भी अधिक परिवर्तनकारी होगा. यदि भाजपा असम में जीत जाती है तो वह निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी. भाजपा को हमेशा से उत्तर भारत के छोटे व्यापारियों की पार्टी समझा जाता रहा है. भाजपा के लिए अपने आधार से अधिक वोट हासिल करने का अर्थ यह होगा कि उसकी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हो गई है.

अब तक किसी दूसरी पार्टी ने वह प्रतिष्ठा हासिल नहीं की जो कांग्रेस को हासिल थी. आज़ादी के पहले दशक में उसने जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के हर राज्य में शासन किया. लेकिन कांग्रेस ने अपने अहंकार, पार्टी के अंदर सुधार से इंकार और एक परिवार पर निर्भरता की वजह से वह हैसियत खो दी. शायद यह अच्छा ही हुआ.■

पश्चिम बंगाल में किसी गैर-बंगाली पार्टी के लिए घुसपैठ करना उचित नहीं है. वामपंथ जिसने दशकों तक बंगाल पर शासन किया और बर्बाद किया, इस बार ममता बनर्जी से हारने के लिए मुक़ाबला करेगा. और इस मुक़ाबले में अपने साथ कांग्रेस को भी रखेगा. गौरतलब है कि जब वामदल यहां सत्ता में थे तो कांग्रेस ने राज्य की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया. तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस की बंगाल इकाई है जो अपनी तरह की गड़बड़ी फैलाएगी लेकिन फिलहाल बंगाल में इसकी पकड़ मज़बूत है. केरल में कांग्रेस का मुक़ाबला अपने पुराने सहयोगी से है. दोनों पक्षों में विभाजन हुआ है और दोनों पर धांधली के आरोप हैं. लेकिन इस बार यहां वाम मोर्चे की बारी है. जहां तक शासन व्यवस्था की बात है तो किसी को कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा.

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने किया खुलासा

धन कमाने में लगे हैं नक्सली

सुनील सौरभ

बंदूक की नली से सत्ता की राह निकालने की बात करने वाले नक्सली अब अपने तमाम सिद्धांतों को दरकिनार कर उच्चवर्गीय लोगों की तरह जीवन यापन करने में लगे हैं. पुलिस की नजर में भले ही शीर्ष नक्सली नेता फरार हैं, लेकिन इन नक्सलियों का परिवार ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जी रहे हैं. नक्सली अपने बेटे-बेटियों को प्रतिष्ठित और महंगे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं. झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने दो वर्षों तक नक्सलियों की सम्पत्ति का ब्यौरा एकत्र करने की खुफिया तरीकों से जांच शुरू की. इस जांच में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें गरीबों-निम्नवर्गीय किसान-मजदूरों का समर्थन प्राप्त कर पुलिस-प्रशासन को चुनौती देने वाले और विकास कार्यों में लेवी वसूलने वाले नक्सलियों की सच्चाई सामने आ गई. झारखंड में अपने संगठन के शीर्ष पद पर काबिज नक्सली गरीबों-मजदूरों का शोषण कर खुद और अपने परिवार को समृद्ध कर रहे हैं और अपने समर्थकों को पुलिस-प्रशासन के निशाने पर छोड़ समाज की मुख्य धारा से वंचित कर रहे हैं. झारखंड के बड़े नक्सली नेता और हार्डकोर ने अपने गृह जिले या राज्य के बड़े शहरों के अलावा राज्य से बाहर सम्पत्ति बनाने में लगे हैं. उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के नक्सली भी झारखंड में सम्पत्ति खरीद कर रखे हुए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर नक्सलियों की सम्पत्ति की जांच में झारखंड के सभी शीर्ष नक्सली नेताओं की सम्पत्ति का पता चला है. झारखंड के अनेक शीर्ष नक्सली बिहार के बड़े शहरों में अकूत सम्पत्ति खरीद कर रखे हुए हैं. इस संबंध में झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस से पूरी जानकारी मांगी है. झारखंड पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके अनुसार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुंदन पाहन एवं उसके परिजनों के नाम झारखंड के बूंडू-तमाड़ में करीब पांच सौ एकड़ खूंटकटी जमीन है, जिसका मूल्य ढाई करोड़ रुपये है. हार्डकोर माओवादी श्यामलाल यादव उर्फ धनंजय का बालूमाथ में दो मंजिला मकान, करीब तीन एकड़ खेती योग्य भूमि, ट्रैक्टर व अन्य वाहन हैं. रातू के सिमलिया में चार डिसमील में बना मकान है जिसकी कीमत करीब 15 लाख है. रांची के कांके क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए पलामू के पांकी निवासी भाकपा माओवादी के हार्डकोर नान्हों मोची उर्फ प्रभात के पास करोड़ों की सम्पत्ति है. उसके दो बच्चे रांची के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई पर प्रति महीने तीस हजार रुपये खर्च होते हैं. पलामू में जमीन और मकान भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उसी प्रकार रांची जिले के राम मोहन सहित 6 हार्डकोर, खूंटी के पांच हार्डकोर, गुमला के बुद्धेश्वर उरांव सहित 12 हार्डकोर, लोहरदगा के शिव नंदन भगत सहित तीन, लातेहार के अजीत उर्फ चार्लिस सहित दस, जमशेदपुर के कान्हू राम मुंडा सहित दो, गिरिडीह के मिसिर बेसरा सहित 17, पलामू के उमेश यादव सहित चार, बोकारो के लालचंद हेंब्रम सहित दो, धनबाद के प्रयाग उर्फ विवेक सहित तीन, चतरा के संजय गंझू सहित आठ, हजारीबाग के उदय गंझू सहित चार, दुमका के पंचान्न राय समेत तीन हार्डकोर माओवादी अपने गृह जिले के अलावा अन्य स्थानों पर अकूत सम्पत्ति बनाने में लगे हैं. इन नक्सलियों को सरकार के द्वारा मुख्य धारा में लाने की बात कही जा रही है. झारखंड पुलिस और सरकार का दावा है कि नक्सली कमजोर हो रहे हैं. लेकिन स्थिति यह है कि समाज से लूटी गई सम्पत्ति और वसूले गए लेवी से नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो रहे बल्कि समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर रहे हैं. गरीबों और मजदूरों के हितैषी बनने का दावा करने वाले नक्सली नेताओं की सच्चाई को पुलिस ने उजागर कर गरीबों-मजदूरों को नक्सलियों की हकीकत से अवगत कराया है. ■

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर नक्सलियों की सम्पत्ति की जांच में झारखंड के सभी शीर्ष नक्सली नेताओं की सम्पत्ति का पता चला है. झारखंड के अनेक शीर्ष नक्सली बिहार के बड़े शहरों में अकूत सम्पत्ति खरीद कर रखे हुए हैं. इस संबंध में झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस से पूरी जानकारी मांगी है.

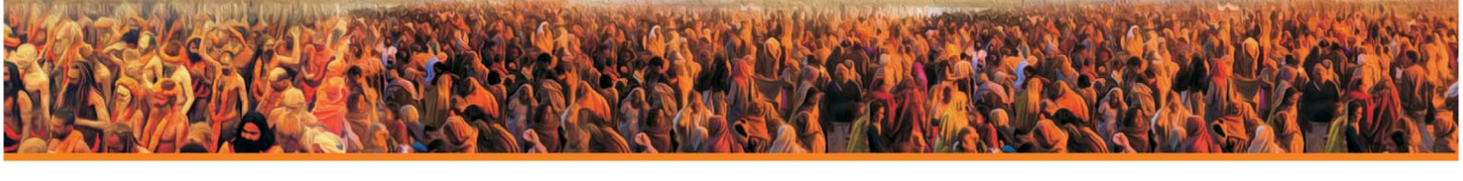

feedback@chauthiduniya.com

सजने लगा नीतीश और मोदी की जंग का मैदान

सरोज सिंह

जनता दल यू के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल की राजनीतिक सक्रियता एक साथ कई संकेत देती है. शरद यादव को समय से पहले ही विदाई देकर उन्होंने जदयू की कमान पूरी तरह अपने हाथों में कर ली. राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी भूमिका पर अब उनके सहयोगियों और विरोधियों दोनों की नजरें टिक गई हैं. दूसरी तरफ बिहार में अपने दल को ठोस और सुनिश्चित सांगठनिक स्वरूप देकर नीतीश कुमार एक विशिष्ट राजनीतिक तंत्र विकसित करने का हरसंभव उपाय कर रहे हैं. नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर कि 2019 में भाजपा का जाना तय है, यह संकेत दे दिया है कि दिल्ली की राजनीति में अब सक्रिय तौर पर रहेंगे. नीतीश ने कह भी दिया कि प्रधानमंत्री के लिए मेरी दावेदारी का फैसला जनता तय करेगी.

अपनी नई भूमिका में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा शासक समूह के सार्थक राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को पेश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते. बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद जदयू के पदाधिकारियों, नेताओं व सांसद और विधायकों की दो-दो औपचारिक बैठकें हुई और इन बैठकों में ये बातें बार-बार साफ हुई हैं. पहली बैठक तो विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की भारी जीत को लेकर धन्यवाद ज्ञापन को लेकर थी. पर दूसरी बैठक पार्टी के सांगठनिक स्वरूप को लेकर रही. जदयू की अभी मार्च के अंतिम हफ्ते में यह बैठक हुई है. इसका मुख्य मकसद नीतीश कुमार के सात निश्चय और शराबबंदी के अभियान में दल के कार्यकर्ताओं की भागीदारी बनाने के लिए उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करना रहा है. मुख्यमंत्री दल का मजबूत सांगठनिक ढांचा तो तैयार कर ही रहे हैं सरकार के जनकल्याण और विकासमूलक कार्यों में कार्यकर्ताओं को भागीदार भी बनाना चाहते हैं. इसके लिए एक साथ दो फ्रंट पर काम किए जाने के संकेत मिले हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

जदयू को सूबे में ठोस सांगठनिक आधार देने की जरूरत पिछले कई वर्षों से शिद्दत से महसूस की जाती रही है. इन बैठकों में दल के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने इसे रेखांकित कर सांगठनिक मामलों का एक रोडमैप बैठक में पेश किया है. सूबे में पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद संपूर्ण क्रांति दिवस अर्थात पांच जून से जदयू का सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इस अभियान के तहत सूबे की सभी पंचायतों में बीस से पच्चीस सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. इनकी मदद से सामान्य सदस्य बनाए जाने हैं. पूरे सूबे में पचास लाख सामान्य सदस्य बनाने का निश्चय किया गया है. इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में दल की तरफ से जन शिकायत कोषांगों का भी गठन करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. यह कोषांग शराबबंदी और नीतीश कुमार के सात निश्चयों के साथ-साथ सरकार के जनकल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर शिकायतों के निपटारे की दिशा में काम करेगा. एक और बात महत्वपूर्ण रही. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों सांसदों को एक विशेष निर्देश दिया है. उनका निर्देश है कि ये लोग जब भी दौरे पर कहीं जाएं तो अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दल के जिला अध्यक्षों को जरूर दें और जिला कार्यालयों में बैठक करें. बैठकों का यह सिलसिला प्रखंड स्तर तक चलाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी जिलों और प्रखंडों में अगले दो महीने में पार्टी कार्यालय खोल लेने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि सूबे में सभी स्तर पर सरकारी समितियों का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा. इन समितियों में महागठबंधन के तीनों दलों के लोगों को शामिल किया जाएगा. इन समितियों में जदयू और राजद के हिस्से में चालीस-चालीस प्रतिशत मेम्बरी होगी जबकि कांग्रेस के खाते में बीस प्रतिशत होगा. बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन खाद्य सुरक्षा आदि की कोई आधा दर्जन सरकारी समितियां हैं जिनको प्रखंड स्तर तक गठित किया जाना है. इन समितियों के जरिए काफी संख्या में कार्यकर्ताओं को सरकारी कामकाज का भागीदार बनाया जा सकता है.

मुख्यमंत्री के ये दोनों निर्देश काफी राजनीतिक महत्व के हैं. लेकिन इन्हें जमीन पर उतारना क्या उतना ही सहज है? इस सवाल का सीधा जवाब देना कठिन है. जदयू के बड़े नेताओं के लिए भी. राज्यस्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक की विभिन्न समितियों में हजारों कार्यकर्ताओं को जगह देकर सरकार के कामकाज में उनकी प्रत्यक्ष-परोक्ष भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है. लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक में यह नहीं बताया कि इन समितियों का गठन कब तक होगा या इसकी प्रक्रिया कब आरंभ होगी. हालांकि जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों का मानना है कि विधानमंडल के सत्रावसान के बाद यह काम आरंभ किया जा सकता है. पर इससे जदयू के ही कई दिग्गजों की असहमति है. उनका मानना है कि यह काम बर्रे के छत्ते को छेड़ने जैसा है. इससे असंतोष निचले स्तर तक पहुंच जाता है. फिर ऐसी समितियों का गठन केवल जदयू के भरोसे नहीं हो सकता है. इस कार्य में महागठबंधन के अन्य घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की भी सक्रिय सहमति चाहिए. उससे नाम नहीं मिलने की स्थिति में समिति का गठन नहीं हो सकता है. मगर कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए ऐसा कहना पड़ता है. दूसरी बात संगठन का काम भी सहज नहीं है. जदयू के पटना आश्रित नेता दावा करते हैं कि सूबे के अधिकांश जिलों में दल का कार्यालय खुल गया है और संगठन जीवन्त व सक्रिय हैं. पर दावा और वास्तविकता में फर्क है. सूबे में वैसे जिलों की संख्या कम ही है जहां दल का जिला कार्यालय अपनी पहचान के साथ सक्रिय है. दल के अधिकांश जिला कार्यालय स्थानीय नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई के अखाड़े में तब्दील हो गए हैं. इनमें कई अघोषित तौर पर बंद पड़े हैं तो कुछ स्थानों पर समानान्तर जिला कार्यालय चल रहे हैं. इन जिलों की संख्या भी कम नहीं है जहां संगठन पर काबिज होने के लिए हिंसक टकराव की खबरें भी आती रहती हैं.

नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर अति संवेदनशील रहे हैं. उनकी यह छवि बार-बार दांव पर आती रही है, पर वह हर बार खुद को संकट से निकाल लेते रहे हैं. इस लिहाज से उनका राजनीतिक कौशल काबिल-ए-तारीफ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धर्मसंकट यह है कि इस बार वह उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं जिनके पंद्रह साल के कार्यकाल को दो साल पहले तक वह कुशासन का प्रतीक बता रहे थे. उनकी सरकार के मंत्री जेल में जाकर सजायाफ्ता आपराधिक सरगना से मिलते हैं. उनका यह भी संकट है कि सरकार में शामिल दल के विधायक मारपीट तो कर ही रहे हैं. बलात्कार जैसे मामले के नामजद अभियुक्त हैं और ऐसे नामजद अभियुक्त विधायक को जेल में ऐश करने का भरपूर मौका मिल रहा है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सजायाफ्ता अपराधी सरगना से मिलने वाले मंत्री या जेल में बिचाराधीन बंदी बलात्कर के आरोपी विधायक को सरकार के ही कुछ बड़े नेताओं का मुखर या मौन संरक्षण हासिल है. मुख्यमंत्री का संकट यह भी है कि वे सूबे में कानून का राज होने की बात निरंतर और जोर से बोल तो रहे हैं पर जनधारणा है कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं. इस धारणा को बदलना जरूरी है. हालांकि कई स्तर पर काम किया जा रहा है, पर हालात में सुधार का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. यह नकारात्मक माहौल नीतीश कुमार के भावी राजनीतिक अभियान में संकट के कारण बन सकते हैं. इसके साथ ही यह भी सही है कि शराबबंदी अभियान की सफलता ऐसे माहौल से निकाल कर उनकी राजनीति को नई उड़ान दे सकती है. यह अगले संसदीय चुनाव 2019 में उनकी बड़ी राजनीतिक पूंजी हो सकती है. एक बड़ा वोट बैंक अनायास उनके साथ हो जाएगा जो राष्ट्रव्यापी असर का हो सकता है. इसके अलावा नीतीश कुमार अब निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात भी जोर शोर से उठा रहे हैं. नीतीश वर्तमान आरक्षण की सीमा पचास फीसदी को भी संविधान में संशोधन कर बढ़ाने की बात कह रहे हैं. जाहिर है शराबबंदी और आरक्षण इन दो मजबूत हथियारों के साथ नीतीश कुमार 2019 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के साथ दो-दो हाथ करना चाहते हैं. नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बिना कांग्रेस के उनकी लड़ाई धारदार नहीं हो सकती. इसलिए उनके रणनीतिकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि यथासंभव विलय और तालमेल का फार्मूला लागू कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यापक मोर्चा बनाया जाएगा और यह कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं. दिल्ली की राजनीति के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)

E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

नौनीहालों की अच्छी सेहत जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. BHAGWAN DAS
(DCH) BAUNSI (BANKA)

अब यह कहना कि नौनीहाल देश के भविष्य होते हैं यह बात पुरानी हो चुकी है। सच मायनों में हम जिन्दगी ही नौनीहालों के भविष्य बनाने के लिए जीते हैं। डॉ. भगवान दास जो कि बांका के बौन्सी के योग्य और कुशल चिकित्सक हैं ने आज हमारे नौनीहालों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को कहा और दौड़ भाग वाली जिन्दगी में बच्चों के परवरिश के प्रति ध्यान देने की बात भी कही। उन्होंने बच्चो के लालन पालन से संबधित कुछ टिप्स दिए। बच्चे का वजन यदि अन्डर वेट हो जिसे एल. पी. डब्लू कहते हैं तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है और पेडियेट्रिक्स डॉक्टर के सलाह पर ही हर कार्य करें। बच्चों को 6 महीने तक मां का दूध ही दें उसके बाद दांत आने तक दाल का पानी मुंग की खिचड़ी, मड़गीला चावल,आलू का चोखा, अंगूर, केला आदि देकर धीरे-धीरे बच्चे को खाने पर लाया जाता है। डॉ. भगवान दास ने ने आगे बताया कि आजकल सरकार बच्चों के टीकाकारण पर काफी जोर दे रही है। और यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि टीकाकरण पुस्तिका के मुताबिक सारे टिके दिलवाये। यह टिके आंगनबाड़ी केन्द्रों से लेकर गांव के छोटे अस्पताल एवं प्रखंड अस्पताल तक निःशुल्क उपलब्ध है। यदि हो सके तो शहर में चिकेन पॉक्स और रोटा वायरस के भी टिके दियें जाते हैं। जिसे दिलवा लेना चाहिए। डॉ दास ने आगे भीषण गर्मी में बच्चों को गर्मी से बचाने की सलाह देते हुए कहा कि धूप में बच्चों को न निकालें साथ ही छोटे बच्चों को न निकलें यदि निकालना ही हो तो अच्छी तरह ढक कर निकालें और पानी की बोतल साथ लेकर चलें। टिप्स -1.यदि शिशु 6 महीने का है तो उसे केवल मां का ही स्तन पान कराएं। 2. गर्मी से बचाने के लिए शिशु को बाहर बिलकुल न लें जाएं। ऐसे में घर कें अंदर कूलर व मध्यम एसी में ही शिशु को रहने दे। 3. यदि शिशु 6 महीने से अधिक का है तो आप उसे हर आधे घंटे में पानी पीलाते रहें। 4. बच्चे को बोतल से दूध न दें। गर्मियों में बोतल चूसने से बच्चे को कई संक्रमण रोग लग सकते हैं। आप बोतल की जगह अपने हाथों से कटोरी और चम्मच के जरिए भी बच्चे को दूध पिला सकती हैं। 5 . बच्चे को समय समय पर डाक्टर की सलाह पर बताए गए टीके लगवाना न भूलें। 3 साल से बड़े बच्चे थोडा नटखट किस्म के होते हैं जिस काम को मना किया जाता है वे उन्हें सबसे पहले करते हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता को बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ताकि वे गर्मी से होने वाले रोगों से बच सकें ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

सभी पार्टियों में अम्बेडकर को अपना दिखाने की रेस

हित नहीं, वोट हथियाने की होड़

[दलित-पक्षधरता की तेज हुई राजनीति को उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के केंद्र में रख कर देखे जाने की जरूरत है. सारी पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महिमामंडित करने की प्रतियोगिता में जुट गई हैं. पूर्व आईपीएस अधिकारी व ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी ने इस राजनीति की अपने दृष्टिकोण से समीक्षा की है. राजनीतिक सहमति और असहमति अपनी जगह है, लेकिन इस कोण पर किसी को असहमति नहीं हो सकती कि मौजूदा समय में व्यक्तिवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, मुद्दाविहीनता में जकड़ते जा रहे समाज को उबारने की आज नितांत आवश्यकता है...]

कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब में दलितवाद की होड़ मची हुई है. सारे दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हथियाने में लगे हैं. इसमें भाजपा सबसे अधिक सक्रिय है. कांग्रेस भी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है. समाजवादी पार्टी भी सरकारी तौर पर डॉ. अम्बेडकर जयंती के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर को मानने वालों को लुभाने की कोशिश कर रही है. इन पार्टियों का अम्बेडकर प्रेम उनका दलितों अथवा डॉ अम्बेडकर के प्रति कोई हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि उनके जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष की धार को कुंद करने का प्रयास है. दरअसल पिछले कुछ साल से दलित नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक इस्तेमाल वोट बटोरने में किया है और अम्बेडकर की विचारधारा को उसके क्रांतिकारी सारतत्व से विरक्त कर दिया है, उसी का यह दुष्परिणाम है कि भाजपा अम्बेडकर को हथियाने का साहस कर पा रही है. कांग्रेस बहुत दिनों से इस प्रयास में लगी है परन्तु उसे भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है.

वर्तमान दलित राजनीति के लिए किसी नए विकल्प की तलाश से पहले वर्तमान दलित राजनीति की दशा और दिशा का विवेचन करना बहुत ज़रूरी है. दलित आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है. इतनी बड़ी आबादी की राजनीति की देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका होनी चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं. वर्तमान में दलितों की कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं. एक बहुजन समाज पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है जिसके कई घटक हैं और तीसरी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है. दक्षिण भारत में भी एक दो छोटी मोटी दलित पार्टियां हैं. फिलहाल बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश तक सिमट कर रह गई है. रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में सक्रिय है जिसके एक गुट के नेता रामदास आठवले और दूसरे के प्रकाश अम्बेडकर. इसका तीसरा गवई गुट हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है. इसके शेष गुट कोई खास अहमियत नहीं रखते हैं.

इन सभी पार्टियों की राजनीति व्यक्तिवादी, जातिवादी, अवसरवादी, सिद्धान्तहीन, मुद्दाविहीन और अधिनायकवादी है. इन पार्टियों के नेता अम्बेडकर और दलितों के नाम पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अलग-अलग पार्टियों से गठजोड़ करते रहते हैं. एक ओर दलित नेता दलितों का भावनात्मक शोषण करके उनका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरी ओर दूसरी राजनीतिक पार्टियां इन नेताओं की कमजोरियों से लाभ उठा कर इन्हें तथा दलितों की विभिन्न उप जातियों को पटा कर उनके वोट हथिया ले रही हैं. परिणामस्वरूप दलित इन दलित नेताओं और दूसरी पार्टियों के लिए वोट बैंक बन कर रह गए हैं. जबकि उनके मुद्दे गरीबी, भूमिहीनता, बेरोज़गारी, अशिक्षा, उत्पीड़न और सामाजिक तिरस्कार किसी भी पार्टी के एजेंडे पर नहीं हैं. वर्तमान दलित राजनीति अपने जनक डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा, आदर्शों और लक्ष्यों से पूरी तरह भटक चुकी है. अब इसे एक नए रैडिकल विकल्प की ज़रूरत है.

वर्तमान दलित राजनीति की मुख्य व्याधियां या कमज़ोरियां पहचानी जा सकती हैं. वर्तमान दलित राजनीतिक पार्टियां कुछ व्यक्तियों की निजी जायदाद बन कर रह गई हैं. वे किसी राजनीतिक सिद्धांत अथवा दलित हित के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी पार्टी से समझौता करने के लिए तैयार रहती हैं. वैसे तो वे सभी डॉ. अम्बेडकर का नाम लेकर दलित हितों की राजनीति करने का दावा करते हैं परन्तु अंतर्वस्तु में वे विशुद्ध व्यक्तिगत लाभ की राजनीति करते हैं. उनके लिए डॉ. अम्बेडकर और दलित केवल साधन मात्र हैं जिनका वे भावनात्मक शोषण करते है. रिपब्लिकन पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण भी व्यक्तिवाद ही था. मायावती तो बसपा की एक मात्र मालिक हैं उसमें कोई दूसरा नेता कोई अहमियत नहीं रखता है. बाकी पार्टियों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य नेता का कोई वजूद नहीं है. डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति पूजा के बहुत खिलाफ थे. डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि मुझे भक्त नहीं अनुयायी चाहिए परन्तु इन पार्टियों में तो भक्तजनों की भरमार है. इसी प्रकार डॉ. अम्बेडकर राजनीतिक पार्टी में आन्तरिक लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे परन्तु दलित पार्टियों में तो घोर व्यक्तिवाद और अधिनायकवाद है. वर्तमान दलित राजनीति सिद्धान्तहीन एवं अवसरवादी गठजोड़ का शिकार है. इसका सबसे बड़ा उदहारण बसपा द्वारा भाजपा से तीन बार किया गया गठजोड़ है और चौथे की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. मायावती का बहुजन अब सर्वजन की शरण में नतमस्तक है और व्यवस्था परिवर्तन की जगह समरसता की घुट्टी पी कर मस्त है. इसी तरह मनुवाद को कोसने वाले इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज अब भाजपा में शामिल हो कर राम नाम की माला जप रहे हैं. रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (ए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने भीम शक्ति और शिव शक्ति का गठजोड़ करके भाजपा की मदद से राज्यसभा में अपने लिए सीट प्राप्त कर ली है. लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भाजपा से गठजोड़ करके अपने लिए हमेशा की तरह मंत्री पद हथिया लिया है.

दलित नेताओं द्वारा किए गए गठजोड़ दलित हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाते हैं. यह बात इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने जिन पार्टियों के साथ गठजोड़ किए हैं उनकी तथा इनकी पार्टी की विचारधार और एजेंडे में कोई समानता नहीं है. दलित नेता अक्सर यह कहते हैं कि डॉ. अम्बेडकर ने भी कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के साथ गठजोड़ किए थे. परन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने यह गठजोड़ दलित हित में किए थे न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए. कांग्रेस के साथ वे संविधान बनाने के लिए इसलिए जुड़े थे, क्योंकि वे संविधान में दलितों को उनका हक़ दिलाना चाहते थे. उन्होंने प्रथम चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ विचारधारा और एजेंडा की समानता के आधार पर ही किया था. डॉ. अम्बेडकर का कांग्रेस के साथ गठजोड़ एक अपवाद स्वरूप था. उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहल के साथ समझौता नहीं किया और जब ज़रूरत समझी कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

वर्तमान दलित राजनीति मुद्दाविहीनता का शिकार है. अपने आप को दलितों का मसीहा कहने वाली मायावती की पार्टी का आज तक कोई भी दलित एजेंडा सामने ही नहीं आया है. उनका कहना है कि आप हमें पहले सत्ता दिलाइये फिर हम आपके लिए काम करेंगे. यह तो दलित राजनीति का दिवालियापन है, जिसका न तो कोई दलित एजेंडा है और न ही कोई राष्ट्रीय एजेंडा. इसीलिए दलित राजनीति न केवल दिशाविहीन है बल्कि इसी कारण दलित नेता अपनी मनमर्जी करने में सफल भी हो जा रहे हैं. एजेंडा बनाने से नेता उससे बंध जाता है और उससे मुकर जाने पर उसकी जवाबदेही हो सकती है. इसीलिए दलित नेता अपने वोटरों से बिना कोई वादा किए अम्बेडकर और जाति के नाम पर वोट लेते हैं. दलित पार्टियों द्वारा कोई भी एजेंडा घोषित न करने के कारण दूसरी पार्टियां भी अपना कोई दलित एजेंडा नहीं बनाती हैं और इतना बड़ा दलित समुदाय राष्ट्रीय राजनीति में केवल वोटर हो कर रह गया है और उसके मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनते. यह वर्तमान दलित राजनीति की सबसे बड़ी विफलता है.

वर्तमान दलित राजनीति पहचान की राजनीति की दलदल में फंसी हुई है. दलित नेता अपनी राजनीति दलित मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि जाति समीकरणों को लेकर करते हैं. वे या तो अपनी-अपनी उपजाति के वोटरों को जाति के नाम पर लुभाते हैं या फिर डॉ. अम्बेडकर के नाम को भुनाते हैं. मायावती तो दलितों पर अपना एकाधिकार जताती हैं. वह यह बात भी बहुत अधिकारपूर्ण ढंग से कहती हैं कि उनका वोट हस्तान्तरणीय है जैसे कि दलित वोटर उनकी भेड़ बकरियां हों, जिन्हें वह जिस मंडी में चाहें मनचाहे दाम में बेच दें. दलित वोटों पर इसी एकाधिकार-भाव के कारण वे पार्टी का टिकट किसी भी माफिया, गुंडे बदमाश और दलित विरोधी को मनचाहे दाम पर बेच देती हैं और उसे दलित वोट दिलवा कर जिता देती हैं. इसी कारण चुनाव जीतने के बाद ये नेता दलितों का कोई काम नहीं करते और खुलेआम कहते हैं कि पैसा देकर टिकट लिया है और वोटरों को पैसा देकर वोट लिया है. दरअसल मायावती ने दलित राजनीति को उन्हीं गुंडे बदमाशों, माफियाओं और दलित उत्पीड़कों के हाथों बेच दिया है जिनसे दलितों की लड़ाई थी. कुछ इसी प्रकार का व्यवहार अन्य दलित पार्टियों के नेता भी अपने वोटरों के साथ करते हैं. लिहाजा, मायावती चाहे जो भी दावा करें, लेकिन हकीकत यही है कि वर्तमान में उनका दलित आधार खिसक गया है.

दलित नेताओं की जातिवादी राजनीति के कारण भी जाति मज़बूत हुई है. दलित 500 से अधिक उपजातियों में बंटे हुए हैं जो एक दूसरे से जातिभेद करते हैं. जाति की राजनीति ने इस विभाजन को और भी उभार दिया है. दलित नेताओं की जाति की राजनीति ने बाबा साहेब के जाति विनाश के एजेंडे को बहुत पीछे धकेल दिया है. बाबा साहेब ने कहा था, मेरे चरित्र और मेरी ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता. लेकिन आज कितने दलित नेता जो यह दावा कर सकते हैं? मायावती का भ्रष्टाचार तो खुली किताब है. ताज कोरिडोर, पत्थर घोटाला, आय से अधिक सम्पत्ति और अब यादव सिंह का मामला तो मायावती के भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख उदहारण हैं. अपनी और दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाने में भी बड़े स्तर का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है. मायावती द्वारा ऊंचे दामों पर टिकट बेचना, अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में पैसे लेना, रैलियों में थैली भेंट करवाना और करोड़ों के नोटों के हार स्वीकार करना क्या है? मायावती के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का पार्टी के कार्यकलापों और कार्यकर्ताओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है. इसके कारण बसपा के काफी कार्यकर्त्ता भ्रष्ट हो गए हैं. इसका एक मुख्य कारण पैसे वाले लोगों द्वारा बसपा का टिकट खरीद कर चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पैसा बांट कर भ्रष्ट बनाना भी है. मायावती के भ्रष्टाचार का खामियाजा उत्तर प्रदेश के दलितों को भुगतना पड़ा है, जिस कारण वे राज्य द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के वांछित लाभ से वंचित रह गए. परिणामस्वरूप 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दलित विकास के मापदंडों (शिक्षा दर, स्त्री-पुरुष अनुपात, शिशुओं का लिंग अनुपात और नियमित रोज़गार आदि) पर बिहार, ओड़ीशा और मध्य प्रदेश के दलितों को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों के दलितों से पिछड़े हैं. इससे स्पष्ट है कि मायावती की सत्ता का लाभ दलितों को नहीं बल्कि दूसरे लोगों को ही मिला है.

वर्तमान दलित पार्टियों की संरचना के विवेचन से स्पष्ट है कि वे एक व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं जो उनकी व्यक्तिगत जागीर हैं, जिसका इस्तेमाल एक व्यापारिक घराने की तरह किया जाता है. इनके अध्यक्ष ही इनके सर्वेसर्वा हैं और उनके अलावा पार्टी में किसी दूसरे नेता का कोई अस्तित्व नहीं है. इनमें हद दर्जे का अधिनायकवाद है. जबकि डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्थापित पार्टियों की एक ख़ास विशेषता यह थी कि इनमें सामूहिक नेतृत्व और अंदरूनी लोकतंत्र का विशेष प्रावधान था. पार्टी के अन्दर व्यक्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था. उनके अंदर नेतृत्व की द्वितीय तथा तृतीय कतार थी. सभी निर्णय सामूहिक विचार विमर्श के उपरांत ही लिए जाते थे. 1952 में शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के संविधान में राजनीतिक पार्टी की भूमिका की व्याख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी का काम केवल चुनाव जीतना ही नहीं होता, बल्कि यह लोगों को शिक्षित करने, उद्वेलित करने और संगठित करने का होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लंबी प्रतीक्षा के बाद भाजपा नेतृत्व को यूपी के लिए मिले मौर्य

पिटे पासे पर ढोल-ताशे!

दीनबंधु ठबीर

उत्तर प्रदेश में चाय बेचने वाले को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाने की लाइन हजम नहीं हो पा रही है. भाजपा को लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरह चाय बेचने वाला फार्मूला हर जगह पर फिट किया जा सकता है, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि चाय बेचने वाले फार्मूले पर केशव प्रसाद मौर्य को फिट किए जाने से यूपी के लोग बिदक पड़े हैं. यूपी के लोगों को पता है कि तथाकथित चाय बेचने वाले मौर्य की आर्थिक औकात क्या है. लिहाजा, प्रदेश के लोगों को झांसा पट्टी देने की नीयत के साथ जिस राजनीति की शुरुआत की जा रही हो उसे लोग गलत मान कर चल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार इस बात पर सवाल भी उठाते हैं कि जब मौर्य को ही प्रदेश अध्यक्ष चुनना था तो भाजपा आलाकमान इतनी देर क्यों लगा रहा था. जब इतनी जद्दोजहद के बाद भी भाजपा को मौर्य ही चुनना था, तो उससे भविष्य के राजनीतिक-गांभीर्य की अपेक्षा कैसे की जा सकती है. इसपर सवाल उठना स्वाभाविक ही है. हर जगह जातीय समीकरण ही फिट नहीं बैठता. बिहार के विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक कार्य कर चुके यूपी भाजपा के एक मंझोले दर्जे के नेता ने कहा कि बिहार में तो जातीय समीकरण बैठाने के चक्कर में दलितों और यादवों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उसका क्या फायदा मिला? अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और बेदाग छवि वाले नेता को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में देखने की इच्छा थी, लेकिन मिला कौन? एक विवादास्पद और दागी छवि वाला व्यक्ति. भाजपा आलाकमान के इस फैसले से ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या छवि और स्थिति बनने वाली है, इसके बारे में अभी से समीक्षा की जाने लगी है.

उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा आलाकमान ने पांच राज्यों के अध्यक्ष बदले हैं. कर्नाटक में भी भ्रष्टाचार के आरोपी येदियुरप्पा ही भाजपा को एकमात्र विकल्प के रूप में दिखाई पड़े. इसी तरह उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य. पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के लिए चुने गए अध्यक्षों पर अधिक विवाद नहीं है. लेकिन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी की नैतिक प्रतिबद्धता और प्राथमिकता पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं. एक अध्यक्ष (कर्नाटक) पर भ्रष्टाचार के गहरे दाग हैं तो दूसरे अध्यक्ष (यूपी) पर हत्या, दंगा फैलाने, धोखाधड़ी करने और सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने जैसे गंभीर मामले हैं. साफ है कि पवित्र और चरित्र की राजनीति का भाजपाई दावा यथार्थ में फिसड्डी ही है. सत्ता पाने की अभिलाषा में भाजपा भी अन्य पार्टियों की तरह किसी भी स्तर पर उतर सकती है. पिछड़ी जाति से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप कर भाजपा ने अपनी यही मंशा जाहिर की है. मोदी लहर में मौर्य भी फुलपुर से सांसद चुने गए थे. उन्होंने मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को हराकर इस सीट को कब्जे में लिया था. मौर्य के चयन के बाद यूपी के लोग आम तौर पर यह सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा जातीय समीकरण साधना चाहती है या हिंदूवादी समीकरण? जातीय समीकरण की रेस में क्या भाजपा मुलायम या मायावती का मुकाबला कर पाएगी? मायावती दलित वोट पर अपना एकाधिकार समझती हैं तो मुलायम पिछड़ों, मुसलमानों और अगड़ी जाति के राजपूतों और भूमिहारों पर अपना अधिकार मानते हैं. ऐसे में मौर्य कहां टिकते हैं, यह देखना है. केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन उनके पास किसी जाति विशेष का कोई बड़ा समर्थन नहीं है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य की पहचान ही तब दर्ज हुई जब उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया.

पहले पासे में मात खाने के बाद अब भाजपा के पास दूसरा कार्ड बचा है चुनावी-चेहरा. यह चेहरा कौन होगा, इसी पर अब केवल प्रदेश क्या देशभर के लोगों की निगाहें लगी हैं. भारतीय जनता पार्टी मिशन-2017 के लिए पार्टी का चेहरा किसे बनाए, इसे लेकर उहापोह में है. भाजपा आलाकमान ऐसे किसी करिश्माई चेहरे की तलाश में है, जिसके साथ उसकी सांगठनिक क्षमता के साथ-साथ ग्लैमर भी हो. पहले तो चुनावी चेहरे के बतौर योगी आदित्यनाथ का नाम खूब चला, लेकिन धीरे-धीरे योगी का नाम पीछे चला गया और इसमें स्मृति ईरानी और वरुण गांधी का नाम ऊपर चलने लगा. भाजपा आलाकमान को इंतजार है कि कांग्रेस शायद प्रियंका गांधी को अपना चुनावी चेहरा बनाए तो भाजपा स्मृति ईरानी पर दांव खेल देगी. अन्यथा कोई अन्य चेहरा सामने लाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम भी चला था, लेकिन उनका खराब स्वास्थ्य खुद इस नाम को दूर तक लेकर नहीं चल पाया. पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने खुद को इस प्रतियोगिता से दूर खड़ा कर लिया. उमा भारती भी इस दांव में नहीं पड़ना चाहतीं. बिहार चुनाव में भाजपा की दुर्गति के बाद कोई भी कद्दावर नेता गरम दूध में हाथ डालने से हिचक रहा है. लिहाजा, भाजपा आलाकमान के पास गिने-चुने विकल्प हैं, लेकिन इस पर भी मंथन और गुंथन जारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

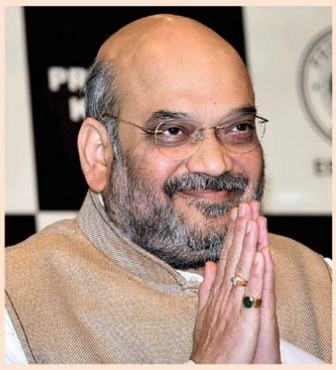

क्रम	धाराएं	विवरण
1	143, 188, 283, 341	Special CJM, Allahabad Case NO.703/2004 Criminal Case NO.177/2003 Date of Cog.-25/03/2004
2	302, 120B	Section 7 C. L. A. Act, Criminal Case No.470/11, PS.- Kokhraj, Janpad-Kaushambi, UP, CJM, Kaushambi, Date of Cog.-07/11/2013 Present Pending in Additional District and Sessions Judge II Kaushambi, ST No.37/2014
3	153A, 188	Criminal Case No.571/11, PS.-Kokhraj, Kaushambi, UP
4	147, 148, 153, 153A, 352, 188, 323, 504, 506	Section 7 C.L.Act, PS.-Manjhanpur, Kaushambi, UP, CJM, Criminal Case NO.218/11, Case No.2187/2012, Cog. Date 07.05.2012
5	147, 295A, 153A	Criminal Case No.82/08, PS.-Mohd.pur Paisa, Kaushambi, UP, CJM Kaushambi, Case No.1281/2002, Cog. Date 05/12/2008
6	420, 467, 465, 171, 188	Criminal Case No.83/08, PS.-Mohd.pur, paisa, Kaushambi, UP, CJM Kaushambi Case No.2715/08, Date of Cog.-24/11/2008
7	147, 352, 323, 504, 506, 392	Criminal Case No.72A/2013, PS.-Manjhanpur, Kaushambi, UP
8	153A, 353, 186, 504, 147, 332	Section 7 C. L. A. Act, PS.-Pashchim Vihar, Kaushambi, UP Criminal Case No.77/96
9	147, 323, 504, 427, 353, 506, 380	Section 3/5 Prevention of Public Property Damage Act and Section 7 C. L. A. Act,PS.-Karnalganj, Allahabad, UP Criminal Case No.431/98, Special CJM Allahabad Case No.1247/02, Cog. No.06.03.2000
10	147, 148, 332, 336, 186, 427	Section 7 C. L. A. Act, PS.-Karnalganj, Allahabad, UP Criminal Case No.02/14
11	143, 353, 341	Criminal Case No.603/13, PS.-Civil Lines, Allahabad, UP

विवादों के सिरमौर...

लंबी प्रतीक्षा के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में बहस फिर तेज हो गई है. इस चयन से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हैरानी है. वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट आरोप है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कोई राय-मशविरा ही नहीं किया और उनकी पूरी तरह उपेक्षा की. जहां तक मौर्य के जातीय समीकरणों का सवाल है, मौर्य कोइरी जाति से आते हैं, जिसका कोई प्रभावकारी असर पिछड़ी जातियों पर नहीं रहा है. मौर्य के बारे में यह भी कहा कि उन्होंने अखबार बेचा और चाय की दुकान भी चलाई. नरेंद्र मोदी की तरह सहानुभूति बटोरने की इस कोशिश को यूपी के लोग यह कह कर खारिज कर देते हैं कि मौर्य करोड़पति हैं. उनका चुनावी हलफनामा ही बताता है कि उनके पास और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की सम्पत्ति है. केशव प्रसाद मौर्य दम्पत्ति पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, कामधेनु लॉजिस्टिक जैसी कई कंपनियों के मालिक हैं. जीवन ज्योति अस्पताल में भी मौर्य दम्पत्ति पार्टनर हैं. कामधेनु चैरिटेबल सोसायटी भी मौर्य की ही है. मौर्य पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक ही उन पर 10 गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें 302 (हत्या), 153 (दंगा भड़काना) और 420 (धोखाधड़ी) जैसे आरोप भी शामिल हैं.

सूखाग्रस्त क्षेत्र में सियासत की बाढ़

पानी की बूंद को तरस रहा बुंदेलखंड

चौथी दुनिया ब्यूरो

राजनीतिक लिहाज से सूबे में शून्य की हैसियत रखने वाला बुंदेलखंड कागजी विकास का एक बड़ा गढ़ बन चुका है. नेता, अफसर, ठेकेदार और दबंग तथा भूमाफिया जिस तरह इस क्षेत्र का चीरहरण कर रहे हैं उसको देखकर शायद कौरवों की आत्मा भी शर्मिंदा हो जाए. रोजगार के मामले में पहले से फिसड्डी यह क्षेत्र कृषि उत्पादन को लेकर भी अब अपने हाथ खड़े कर चुका है. यहां अब न पीने का पानी है और न भूख मिटाने को भोजन, तंगहाली यहां अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. पलायन के रिकॉर्ड ने भी हदें पार कर दी हैं. भीषण विद्युत कटौती और पचास के आंकड़े को छूते तापमान के बीच यहां कुछ शेष बचा है, तो वह है सिर्फ थोथी सियासी नौटंकी! एक ऐसी नौटंकी जिसमें सरकार निर्देशक की भूमिका में है और प्रशासनिक तंत्र मंचन कर रहा है, जबकि जनता को बेबसी की तालियां ठोकने का काम सौंपा गया है.

बुंदेलखंड पांच नदियों का क्षेत्र रहा है, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है. इस क्षेत्र में कई छोटी नदियां और काफी संख्या में पोखर थे, लेकिन अवैध बालू खनन के कारण छोटी नदियों की हत्या कर दी गई और भूमाफियाओं ने पोखरों को भर कर इमारतें खड़ी कर दीं. ऐसे में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. भूजल स्तर के काफी नीचे होने की जानकारी के बावजूद सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया. लोगों को भीषण पेयजल के संकट का सामना करना पड़ रहा है. कुंओं, तालाबों की व्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया. भूजल का इस कदर दोहन किया गया कि वहां आर्सेनिक और नमक तक निकल आया. परंपरागत कुएं और ट्यूबवेल में तो अब पानी रहा भी नहीं. तालाब सब बर्बाद हो गए. तालाबों को पुनर्जीवित करने के नाम पर धंधा जरूर चल रहा है. बुंदेलखंड विकास मोर्चा के आशीष सागर कहते हैं कि भू-जल पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है और पृथ्वी पर होने वाली जलापूर्ति अधिकतर भू-जल पर ही निर्भर है, लेकिन इसका इतना दोहन हुआ है कि पूछिए मत. अब भूजल की उपलब्धता को लेकर भारी कमी महसूस की जा रही है, लेकिन उपाय कुछ नहीं किया जा रहा. पूरे क्षेत्र में भूजल का स्तर तेज गति से नीचे सरकता चला गया और आज पानी बचा ही नहीं.

सूखे और भूखे बुंदेलखंड पर हो रही सियासत बेहद शर्मसार कर देने वाली है. कहने को तो यहां के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है, बावजूद इसके यह क्षेत्र जितना बेबस और लाचार पहले था उतना ही आज भी है. इस क्षेत्र को बदहालमुक्त करने जैसी नौटंकी के बीच जिस तरह का कागजी तमाशा यहां हो रहा है वह शायद देश में अपनी तरह की इकलौती और अनूठी नजीर कही जा सकती है. आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर अफसरशाही और सरकार की नुमाइंदगी का दंभ भरने वाले स्थानीय खद्दरधारी आपसी जुगलबंदी की दम पर खुलेआम शासकीय इमदाद को लूट रहे हैं. जबकि यहां की तीन करोड़ आबादी आज भी विकास की आस लगाए बैठी है. बुंदेलखंड के बिगड़े हालातों को हथियार बनाकर राजनीतिक हित साधने जैसी कोशिशों के बीच जो तमाशेबाजी की जा रही है उसने राजनीति की परिभाषा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. इस बदली परिभाषा को समझने के लिए जरूरी है कि हम बुंदेलखंड की मौजूदा परिस्थितियों और यहां के कथित विकास की असलियत को गंभीरता से समझें. सात जनपदों और दो मंडल वाले बुंदेलखंड में किस प्रकार का विकास हो रहा है इसका अंदाजा अरुणोदय संस्थान नामक संस्था की उस सर्वे रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें यहां के मृतक किसानों की संख्या दो हजार से अधिक दिखाई गई है. इस समाजिक संगठन के मुखिया समाजसेवी अभिषेक मिश्रा का स्पष्ट कहना है कि यदि यहां इमानदारी से विकास किया जाता तो इतने किसानों की मौत हरगिज न होती. इनके मुताबिक आत्महत्या करने वाले किसानों में सर्वाधिक संख्या महोबा जनपद की है.

बुंदेलखंड में पानी एक बड़ी समस्या के तौर पर स्थापित हो चुका है. एक ओर जहां पर्याप्त जल संसाधन न होने के कारण किसान तबाह हो रहे हैं, वहीं गहराते पेयजल संकट ने यहां कई गांवों के युवा ग्रामीणों के घर बसाने जैसे सपनों पर पानी फेर दिया है. हमीरपुर जिले का गुसियारी गांव हो या फिर बांदा का माखनपुर, इस तरह के कई गांवों में सिर्फ इसलिए कोई अपनी लड़की नहीं ब्याहता कि वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है. जल संचयन को लेकर गंभीर अपना तालाब अभियान समिति के संयोजक पुष्पेंद्र भाई का मानना है कि पानी को लेकर आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए प्रशासन की बदनीयत असल वजह है. इनकी मानें तो प्रशासनिक तंत्र ने जितनी तत्परता सरकारी धन को ठिकाने लगाने में दिखाई, उससे आधी गंभीरता धरातल पर दिखाई होती तो बुंदेलखंड में पानी ही पानी होता. बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व महोबा में कमरत कर रहे पुष्पेंद्र भाई कहते हैं कि यहां के घट चुके भूगर्भ जल स्तर को फिर से हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब शासन खेत तालाब योजना का दायरा बढ़ाए. अभी तक समूचे बुंदेलखंड में 2000 तालाब बनाने को स्वीकृति दी गई है, पर यह संख्या नाकाफी है. अपना तालाब अभियान समिति के प्रयास से प्रारम्भ हुई इस योजना को आवंटित धन में भी इजाफे की दरकार है. बुंदेलखंड के विकास को लेकर हो रही प्रशासनिक नौटंकी की पोल महोबा में चल रहा रोटी बैंक और क्रमिक उपवास कर रहा बुंदेली समाज खोल रहा है. कहने को तो यहां सरकार ने मुफ्त में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा मसौदा तैयार किया है, पर रोटी बैंक जैसी संस्था का महोबा शहर में 200 परिवारों को भोजन कराने जैसा दावा सरकार की उस योजना पर प्रश्नचिन्ह लगाता नजर आ रहा है. ■

बुंदेलखंड को अब एनडीआरएफ से मदद

सूखे की विकट स्थिति से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत सूखा राहत के रूप में 1,303 करोड़ रुपये मिलेंगे. मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया गया. यह भी तय किया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को तेज किया जाएगा और इसका विस्तार सभी ब्लॉकों में किया जाएगा ताकि आय का वैकल्पिक स्रोत सृजित हो सके. इसके अलावा बुंदेलखंड में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के तहत प्राथमिकता से पानी टंकियों के निर्माण, कुओं की खुदाई, खेतों में तालाबों का निर्माण कराया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों पर आयोजित इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी हिस्सा लिया. बैठक में तय किया गया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र के दीर्घावधिक और समेकित विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करेंगी. मोदी ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में सूखे की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की जाए. बुंदेलखंड पर हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उनकी टीम ने प्रेजेंटेशन दिया. केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के सचिव भी बैठक में मौजूद थे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश को सूखा राहत के लिए एनडीआरएफ से 1,304 करोड़ रुपये देने की बात तय हुई. आधिकारिक तौर पर बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर रखा है.

तेजी से सोख रहे हैं भू-जल

सूखे की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश में नदियों का पानी नदारद है और तालाब विलुप्त हैं. भूजल का अंधाधुंध दोहन जारी है. भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के 120 विकासखंडों में भूजल का अतिदोहन किया जा रहा है. बाकी 659 विकासखंडों में भी भूगर्भ जल लगातार नीचे गिर रहा है. इससे पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. अगर भूगर्भ जल पर निर्भरता कम नहीं की गई, तो आने वाले वर्षों में सूबे को जबरदस्त जलसंकट का सामना करना पड़ेगा. बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस, मथुरा, आगरा, रामपुर, सहारनपुर, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, बांदा, वाराणसी, जौनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और आगरा का सबसे ज्यादा इलाका भूगर्भ जल की गिरावट की चपेट में है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हालत और खस्ता होने वाली है. लखनऊ में 60 प्रतिशत मांग भूगर्भ जल से पूरी हो रही है. मेरठ और अलीगढ़ जैसे शहर तो 100 प्रतिशत मांग भूगर्भ जल से ही पूरी करते हैं. भूगर्भ जल के संरक्षण केलिए फरवरी 2013 में नीति आई. इसके अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने मकान में रूफ-टॉप वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाना अनिवार्य है. लेकिन इस दिशा में कोई भी काम ठोस शक्ल नहीं ले सका.

feedback@chauthiduniya.com

भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत

रवींद्रनाथ टैगोर और क़ाज़ी नजरुल इस्लाम भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत हैं. साहित्य के क्षेत्र में इन्हें एक जैसा ही सम्मान दोनों देशों में हासिल है. इतना ही नहीं, बांग्लादेश में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद को लोग उसी आदर और सम्मान से याद करते हैं, जितना कि भारत में.

पतिसर स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर संग्रहालय

संग्रहालय प्रांगण में लगी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मूर्ति

अभिषेक रंजन सिंह

ढाका समेत कई शहरों की यात्राएं पूरी करने के बाद हमें नौगांव जाना था. साल 1984 से पहले यह राजशाही जिले के अंतर्गत था. रात करीब पौने ग्यारह बजे पुराना ढाका बस स्टैंड से यात्री बस में सवार होकर हम लोग नौगांव के लिए रवाना हुए. भारत की तुलना में यहां रेल नेटवर्क का उतना विस्तार नहीं हो पाया है. नतीजतन आवाजाही के लिए यहां लोगों को बसों का सहारा लेना पड़ता है. नौगांव राजधानी ढाका से लगभग ढाई सौ किलोमीटर दूर है. रात करीब दो बजे हमारी बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी एक सहयात्री ने बताया, यह बंगबंधु सेतु है, जो एशिया का सबसे लंबा सेतु है. पद्मा नदी पर बना यह सेतु बोगरा और सिराजगंज जिलों को आपस में जोड़ता है.

सुबह पौने पांच बजे अपने नियत समय पर बस नौगांव पहुंची. पहले से वहां खड़ीं दो कारें और कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे थे. कार में सवार होकर हम लोग गांव पतिसर के लिए रवाना हुए. इस गांव की दूरी नौगांव जिला मुख्यालय से पच्चीस किलोमीटर है. सुबह होने की वजह से सड़क पूरी तरह खाली थी. दोनों तरफ धान के खेत और उसके बीच में काली सड़क काफी सुंदर दिख रही थी. कार में सवार ट्रेड यूनियन से जुड़ी नेता लवली यासमिन ने बताया कि पतिसर में मशहूर बांग्ला साहित्यकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों की जमींदारी थी. इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का गृह जिला बोगरा भी नौगांव से ज्यादा दूर नहीं है.

सुबह ठीक छह बजे हमारी कार पतिसर स्थित डाकबंगले में रुकी. भारत में डाकबंगले अमूमन शहरों में होते हैं, लेकिन बांग्लादेश के एक गांव में सर्किट हाउस का होना इस गांव की अहमियत बताने के लिए काफी थी. गाड़ी से उतरते वक्त सबके चेहरे पर थकान और आंखों में नींद की झलक साफ दिख रही थी. अचानक नौजवानों का एक समूह जय बांग्ला-जय बंगबंधु का नारा लगाते डाकबंगला परिसर में दाखिल हुए और उन्होंने हमारा स्वागत किया. करीब तीन घंटे के विश्राम के बाद हम डाकबंगला के बाहर रवींद्र सरोवर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने खजूर का रस पीने के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में सूर्योदय से पहले उतारा गया खजूर का रस लोग पीना पसंद करते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, भारत के कई राज्यों में नशे के लिए खजूर के रस का प्रयोग किया जाता है.

दोपहर के भोजन से पहले गांव में घूमने और स्थानीय लोगों से बात करने पर काफी नई जानकारियां मिलीं. बदलते वक्त के साथ बेशक इस गांव में भी काफी बदलाव हुए, लेकिन पतिसर की पहचान आज भी कवि रवींद्रनाथ ठाकुर से ही होती है. साल 1830 में रवींद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ ठाकुर ने अंग्रेजों से यहां की जमींदारी खरीदी थी. नागौर नदी के तट पर बसे इस गांव के लिए राजधानी ढाका समेत देश के विभिन्न जिलों से आवागमन की अच्छी सुविधा है. पतिसर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अतरई रेलवे स्टेशन है. ब्रिटिश भारत के समय निर्मित इस स्टेशन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है. महात्मा गांधी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई बड़े नेताओं के आगमन का गवाह रहा है यह स्टेशन. रवींद्रनाथ टैगोर पहली बार वर्ष 1891 में पतिसर आए थे. वह बेशक एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पेशा जमींदारी और काश्तकारी से उन्हें कोई खास सरोकार नहीं था. रवींद्रनाथ टैगोर प्रकृति प्रेमी थे और शायद यही वजह है कि उनकी कई रचनाओं में प्रकृति और उसकी अप्रतिम सुंदरता का विस्तारपूर्वक जिक्र है. रवींद्र सरोवर के चारों तरफ उन दिनों आम, पलाश और पीपल के कई पेड़ मौजूद थे. गुरु जी ने उन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर कई कालजयी उपन्यास, कहानियों और कविताओं की रचना की. गांव से होकर बहने वाली नागौर नदी, जिसमें इन दिनों पानी नहीं है, उसके किनारे बैठकर भी उन्होंने कई रचनाएं लिखीं. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर संग्रहालय के प्रभारी मोहम्मद सोहेल इम्तियाज़ बताते हैं, वर्ष 1913 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें मिला यह सम्मान पतिसर वासियों के लिए भी बेहद गर्व का विषय था. ग्रामवासियों के आग्रह पर रवींद्रनाथ टैगोर पतिसर आए और उन्होंने अपने रैयतों को संबोधित किया. साल 1937 में वह बांग्ला त्यौहार पुण्य उत्सव के मौके पर आखिरी बार पतिसर आए थे. इसके कुछ समय बाद उनका निधन हो गया और उसके बाद 1947 में पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया. ज़मीन और नक्शे पर भले ही भारत और पाकिस्तान बन गए हों और उनके बीच संपत्तियों के बंटवारा हो गया हो, लेकिन दोनों देशों की साझी विरासत को न तो अंग्रेज ताकसीम (बांट) कर पाए और न ही उन दिनों के महत्वाकांक्षी नेता. राजशाही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मोहम्मद अमीरूल मोमिन चौधरी बताते हैं कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की हुकूमत यहां की बांग्ला भाषी जनता पर जबरन उर्दू थोपना चाहती थी. उनकी नज़रों में हमारी भाषा और सहित्य का कोई मतलब नहीं था. उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और चौबीस वर्षों बाद यानी 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ. नए देश के गठन के बाद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का सम्मान और बढ़ गया, जब उनके लिखे गीत आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया.

पतिसर में ढाई एकड़ ज़मीन पर उनकी स्मृति में बना भव्य संग्रहालय है. इस संग्रहालय में उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मौजूद हैं. जिस पलंग और कुर्सी पर कभी गुरु जी बैठा करते थे, वह इस संग्रहालय में आज भी अच्छी स्थिति में है. इस संग्रहालय में उनके जीवन से जुड़ी करीब साढ़े तीन सौ वस्तुएं हैं, जो उचित देखरेख की वजह से आज भी अच्छी स्थिति में हैं. रवींद्र सरोवर के किनारे उनकी एक भव्य प्रतिमा भी है, जिसे देखने पूरे बांग्लादेश और भारत से हजारों लोग हर साल आते हैं. पतिसर आने वाले सैलानियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए स्थानीय जिला प्रशासन ने संग्रहालय से चंद कदम दूर एक डाकबंगला भी बनाया है. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस डाकबंगले में कुल 22 कमरे हैं. इसराफिल आलम बांग्लादेश अवामी लीग के स्थानीय सांसद हैं. उनके मुताबिक, रवींद्रनाथ टैगोर की वजह से इस गांव की पहचान पूरे विश्व में है. दुनिया के अलग-अलग कोने से लोग यहां घूमने और उनके विषय में शोध करने आते हैं. खासकर उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर यहां काफी भीड़ रहती है.

रवींद्रनाथ टैगोर और क़ाज़ी नजरूल इस्लाम भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत हैं. साहित्य के क्षेत्र में इन्हें एक जैसा ही सम्मान दोनों देशों में हासिल है. इतना ही नहीं, बांग्लादेश में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद को लोग उसी आदर और सम्मान से याद करते हैं, जितना कि भारत में. महात्मा गांधी को लोग यहां किस तरह याद करते हैं, उसका जीवंत उदाहरण पतिसर से 10 किलोमीटर दूर अतरई के गांधी आश्रम में देखने को मिला. लगभग पंद्रह बीघा ज़मीन में बना यह आश्रम काफी पुराना है. गांधी आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम बताते हैं कि साल 1939 में राजशाही डिवीजन के कई जिलों में भीषण बाढ़ आई थी. बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए महात्मा गांधी यहां आए थे और इसी आश्रम में वह कई दिनों तक रहे. आश्रम में उनका चरखा व कई अन्य वस्तुएं आज भी मौजूद हैं. आश्रम के उपाध्यक्ष निरंजन कुमार दास बताते हैं कि महात्मा गांधी से पहले प्रफुल्ल चंद्र रॉय और नेताजी सुभाषचंद्र बोस 1922 में यहां आए थे. महात्मा गांधी को अतरई से काफी लगाव था, क्योंकि भारत विभाजन के समय नोआखाली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में काफी लोग मारे गए थे, जबकि नौगांव, राजशाही, बोगरा और सिराजगंज में खून-खराबे की कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई थी. नोआखाली से लौटते वक्त महात्मा गांधी अतरई स्थित इसी आश्रम में प्रार्थना सभा की. साथ ही उन्होंने यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आपसी भाईचारे की बहुत प्रशंसा की थी. निरंजन के मुताबिक, बांग्लादेश के नागरिक महात्मा गांधी का काफी सम्मान करते हैं. यहां होने वाले सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के पोस्टर-बैनरों में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और महात्मा गांधी की तस्वीरें देखी जा सकती हैं.

बांग्लादेश में शिक्षा के प्रति लोगों में कितनी जागरुकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले नौगांव जिले में ही 95 शैक्षणिक संस्थान हैं. यही स्थिति पूरे बांग्लादेश में है. यहां की मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान के मुक़ाबले कहीं ज्यादा शिक्षित हैं.

गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने गांधी आश्रम में लाखों रुपये की लागत से एक नए भवन का निर्माण कराया. ज्यादातर लोग रवींद्रनाथ टैगोर को एक महान साहित्यकार के रूप में जानते हैं, लेकिन यह बेहद कम लोगों को यह मालूम है कि वह एक समाजसेवी भी थे. पूर्वी बंगाल में उन्होंने अपने निजी संपत्ति खर्च कर कई विद्यालयों की स्थापना की. इतना ही नहीं, वर्ष 1905 में उन्होंने राजशाही जिले में एक कृषि बैंक भी बनाया, जिसका फायदा स्थानीय किसानों को आज भी मिल रहा है.

बांग्लादेश में जिस तरह गांधी, टैगोर, सुभाषचंद्र बोस और क़ाज़ी नजरूल इस्लाम को याद किया जाता है, दरअसल वह दोनों देशों की साझी विरासत है. इसकी बुनियाद इतनी मजबूत है कि इस पर कोई मजहबी रंग नहीं चढ़ सका. वैसे भी धर्म और संस्कृति में काफी अंतर है. आज धर्म का इस्तेमाल समाज को तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन संस्कृति समाज का जोड़ने का काम करती है. हालांकि, इन दिनों इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश को नफरत और हिंसा की आग में झोंकने की कोशिशों में जुटे हैं. पिछले दिनों ढाका में युवा ब्लॉगर नजीमुद्दीन समद की हत्या कर दी गई. समद ढाका स्थित जगन्नाथ विश्वविद्यालय में एलएलएम की पढ़ाई कर रहे थे. बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे गैर-बराबरी के खिलाफ वह सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे. उनकी यह उदारवादी छवि उनकी मौत का कारण बनी. पिछले साल भी बांग्लादेश में कई ऐसे ब्लॉगरों की हत्या हुई, जो बांग्लादेश में मुखर होकर अपने विचार प्रकट करते थे. बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति वाकई खराब है और ऐसी सूरत में वहां गांधी, टैगोर और क़ाज़ी नजरूल इस्लाम की प्रासंगिकता काफी बढ़ जाती है. ■

पतिसर स्थित डाकबंगला

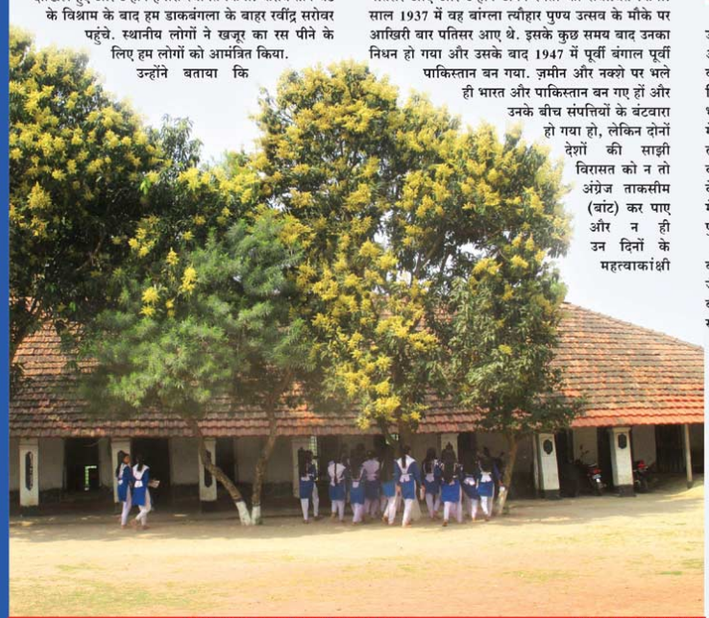
नौगांव जिले में स्थित कालीशाम रवींद्रनाथ इंस्टीट्यूशन

सभी फोटो : अभिषेक रंजन सिंह

feedback@chauthiduniya.com

प्रीति की वापसी

भैयाजी सुपरहिट के साथ कमबैक कर रही हैं प्रीति जिंटा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के फैंस के लिए अच्छी ख़बर है. वह जल्द ही बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं, वो भी सनी देओल जैसे दमदार हीरो के साथ. फिल्म का टाइटल भी काफी मज़ेदार है *भैयाजी सुपरहिट*. काफी लंबे अरसे के बाद इस फिल्म को फिर से शुरू किया जा रहा है. अब ख़बर है कि जल्द ही इस फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू होगी. *भैयाजी सुपरहिट* के डायरेक्टर नीरज पाठक ने बताया, प्रीति ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने पर हामी भर दी है. यह शूटिंग बनारस में 40 दिन चलेगी. इस बीच, सनी के प्रवक्ता ने भी बताया कि वो भी उसी समय से शूटिंग शुरू करेंगे.

भैयाजी सुपरहिट के लिए प्रीति जिंटा शादी के बाद भारत लौट रहीं है. 42 वर्षीय प्रीति इन दिनों लॉस एंजिलिस में जीन गुडइनफ के साथ अपनी नई शादीशुदा जिंदगी का आनंद उठा रही हैं. जीन एक बिजनेसमैन हैं और उन्होंने पिछले महीने ही प्रीति से शादी की है. प्रीति आख़िरी बार 2013 की फिल्म *इश्क इन पेरिस* में नज़र आई थीं. प्रीति और सनी पहले भी फिल्मों में एक साथ नज़र आ चुके हैं.■

भैयाजी सुपरहिट के डायरेक्टर नीरज पाठक ने बताया, प्रीति ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने पर हामी भर दी है. यह शूटिंग बनारस में 40 दिन चलेगी.

प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन और अनुपम खेर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों से विभिन्न क्षेत्रों की 56 हस्तियों को सम्मानित किया. इनमें बॉलीवुड से अनुपम खेर, अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा के नाम शामिल थे. सिनेमा जगत में अहम योगदान देने के लिए एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के अलावा फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और एस.एस. राजमौली को पद्म श्री पुरस्कार से नवाज़ा गया. इनके अलावा गुलाबो सपेरा, मालिनी अवस्थी और प्रतिभा प्रहलाद को भी पद्म श्री पुरस्कार दिया गया. बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, राम सुतार, गायक उदित नारायण को पद्म भूषण से नवाज़ा गया. इसी तरह पद्मश्री से प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, अजय देवगन, दीपिका कुमारी और मोहम्मद इम्तियाज़ कुरैशी सहित 43 हस्तियों को सम्मानित किया गया है.■

करण से 30 अप्रैल को शादी करेंगी बिपाशा!

करण सिंह ग्रोवर पहले दो बार शादी कर चुके हैं और दोनों बार उनका तलाक हुआ. उनकी पहली शादी टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से हुई थी और दूसरी बार भी उन्होंने टीवी की एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को चुना था.

दो बार तलाक ले चुके करण सिंह ग्रोवर की मां दीपा सिंह ने बिपाशा बसु और उनके रिश्ते के लिए हामी भर दी है. ये कपल 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. करण और बिपाशा ने शादी के लिए मुंबई के एक उपनगरीय होटल को भी सेलेक्ट कर लिया है. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है.

करण की मां को पसंद नहीं थी बिपाशा

ख़बरों के मुताबिक करण की मां दीपा सिंह को बिपाशा पसंद नहीं थी. उन्होंने बहू के तौर पर बिपाशा पर अपनी मुहर नहीं लगाई थी. वह बिपाशा के पिछले असफल रिश्तों को देख रही थीं. करण से पहले उनकी ज़िंदगी में डीनो मोरिया, जॉन अब्राहम और हरमन बवेजा रह चुके हैं. यह देखकर करण की मां को लगता था कि बिपाशा उनके बेटे को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं. हालांकि, वे अचानक मान कैसे गईं, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है.■

फ्लैशबैक

कंडक्टर से एक्टर बने जॉनी वॉकर

"फिल्म प्यासा में जॉनी पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी का चंपी मालिश वाला गीत सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए काफी पॉपुलर हुआ. अजी बस शुक्रिया फिल्म में गाना बना सच कहता है जॉनी वॉकर, घर की मुर्गी दाल बराबर. हास्य भूमिकाओं में इस कदर जमे कि उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर मिस्टर कार्टून एम.ए., जरा बचके, रिक्शावाला, मिस्टर जॉन जैसी फिल्में बनने लगीं."

फिल्म *सीआईडी* का गीत *ऐ दिल है मुश्किल जीना यहां, ज़रा हटके ज़रा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान*, जो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था. गीत में ट्राम और मिलों का जिक्र है, जो अब नहीं हैं. अब लोकल ट्रेनें और मॉल हैं. मुंबई का चेहरा काफी बदल चुका है, मगर आम आदमी की मुश्किलें वही हैं और हां, बेस्ट की बसें भी वही हैं. ऐसी ही एक बस में कंडक्टर हुआ करते थे बदरुद्दीन काज़ी. उनके पिता जमालुद्दीन काज़ी इंदौर में मिल मज़दूर हुआ करते थे. आर्थिक संकट के कारण जब लंबे-चौड़े परिवार का भरण-पोषण कठिन हुआ, तो सपरिवार मुंबई (तब बॉम्बे या बम्बई) चले आए.

बदरुद्दीन को बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई. बदरुद्दीन को शुरू से सिनेमा का जुनून था और लोगों की नकल उतारने में माहिर थे, सो बस में मिमिक्री से यात्रियों का मनोरंजन करते रहते थे. माहिम में एक एक्स्ट्रा सप्लायर ने देखा, तो फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम ऑफर किया. भीड़ में खड़े होने के लिए उन्हें 5 रुपये मिलते, जिसमें से एक रुपया सप्लायर ले लेता. शूटिंग के बीच में फुर्सत के दौरान सितारों के मनोरंजन के लिए लोग अक्सर बदरू को बुला लेते और लतीफे सुनाने को कहते. *हलचल* की शूटिंग पर बलराज साहनी ने जब बदरू को दिलीप कुमार, याकूब जैसे स्टार्स का मनोरंजन करते देखा, तो उन्हें बुरा लगा. उन्होंने बाद में बुलाकर बदरू से कहा, तुम कलाकार हो, भांड नहीं. कला की इज्जत करना सीखो.

बदरू ने जब अपनी मजबूरी बताई, तो बलराज साहनी ने उन्हें एक आइडिया सुझाया और अगले दिन गुरुदत्त के ऑफिस में आने को कहा. बलराज साहनी उन दिनों *बाज़ी* की स्क्रिप्ट लिख रहे थे. अगले दिन गुरुदत्त अपने ऑफिस में चेतन आनंद के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे कि बदरुद्दीन अचानक आ धमके और शराबी की ऐक्टिंग शुरू कर दी. उन्होंने न सिर्फ धमाल मचाया, बल्कि गुरुदत्त के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी. हरकतें जब हद को पार करने लगीं, तो गुरुदत्त को गुस्सा आ गया. उन्होंने स्टॉफ को बुलाया और शराबी को बाहर सड़क पर फेंक आने का फरमान जारी कर दिया. तभी बलराज साहनी हंसते हुए वहां आ पहुंचे और गुरुदत्त को सारा माजरा

समझाया. गुरुदत्त इतने खुश हुए कि पीठ थपथपा कर न केवल उनकी ऐक्टिंग की दिल खोलकर तारीफ की और *बाज़ी* में फौरन एक रोल दिया, बल्कि बदरुद्दीन काज़ी को जॉनी वॉकर (नामी शराब) का नया फिल्मी नाम दे डाला. गुरुदत्त ने अपनी अन्य फिल्मों *आर पार* , *मिस्टर ऐंड मिसेज 55*, *सीआईडी*, *प्यासा*, *कागज के फूल* में भी जॉनी वॉकर को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दीं. *प्यासा फिल्म* में उन पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी का चंपी मालिश वाला गीत *सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए* काफी पॉपुलर हुआ. *अजी बस शुक्रिया* में गाना बना *सच कहता है जॉनी वाकर, घर की मुर्गी दाल बराबर*. हास्य भूमिकाओं में इस कदर जमे कि उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर *मिस्टर कार्टून एम.ए., जरा बचके , रिक्शावाला, मिस्टर जॉन* जैसी फिल्में मिलने लगीं. एक फिल्म का तो नाम ही *जॉनी वॉकर* था.

लोकप्रियता का यह हाल था कि छोटे भाई कमालुद्दीन काज़ी ने अपना नाम टॉनी वॉकर कर लिया. *आर पार* की शूटिंग के दौरान नायिका शकीला की छोटी बहन नूरजहां से हुई मुलाकात मुहब्बत और फिर गुपचुप निकाह में बदल गई. बांद्रा और फिर अंधेरी में बने अपने बंगले का नाम नूर विला रखा. जॉनी ने 35 वर्षों में करीब 325 फिल्में की और सिनेमा से संन्यास ले लिया, मगर ऋषिकेश मुखर्जी के आग्रह पर *आनंद* और गुलज़ार के आग्रह पर *चाची 420* की भावनात्मक भूमिकाएं उन्हें स्वीकार करनी ही पड़ीं. रजनीकांत अक्सर कहा करते थे कि बस कंडक्टर से ऐक्टर बनने की प्रेरणा उन्हें जॉनी वॉकर से मिली.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

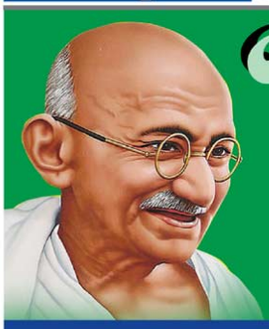

"शराब के ठेके लोकतन्त्र का कलंक और शराब अभिशाप है यदि देश में शराबबंदी लागू नहीं हुई तो हमारी स्वतंत्रता गुलामी बनकर रह जायेगी.

-गांधीजी"

जन नेता महापुरुषों की सिर्फ मूर्तियां नहीं लगाते, बल्कि उनके विचारों को नीतियों में तब्दील करते हैं.

शराबबंदी को जन-आंदोलन बनाने और शराब माफिया, भू-माफिया व खनन माफिया के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार जी के शंखनाद का उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा ज़ोरदार स्वागत

स्थान : रवींद्रालय
चारबाग़, लखनऊ

दिनांक : 15 मई 2016

समय : 12 बजे

निवेदक : विनोद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मंच
शेखर दीक्षित, अध्यक्ष, किसान मंच उत्तर प्रदेश